

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 2015/अग्रहायण 14, 1937

No. 321]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 2015/AGRAHAYANA 14, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2015

अंतिम जांच परिणाम (निर्णायक समीक्षा जांच)

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेलामाईन" के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने संबंधी निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. संख्या 15/17/2014-डीजीएडी.- समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. यत: निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाईन के आयातों पर दिनांक 27.02.2004 की अधिसूचना संख्या 14/16/2003-डीजीएडी द्वारा अनन्तिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने दिनांक 02.04.2004 की अधिसूचना संख्या 53/2004-सीमा शुल्क द्वारा ऐसा अनन्तिम शुल्क लगाया था। प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाईन (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक 5078 GI/2015

पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने वाले अंतिम जांच परिणाम को जारी किया था और भारत सरकार ने दिनांक 16 नवम्बर, 2004 की सीमा शुल्क की अधिसूचना सं. 107/2004-सीमा-शुल्क द्वारा ऐसा सुनिश्चित शुल्क लगाया था।

- 3. यत: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उसके बाद दिनांक 21.11.2008 की अधिसूचना संख्या 15/29/2008-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 20.11.2009 की अधिसूचना संख्या 15/29/2008-डीजीएडी द्वारा पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी। संबद्ध देश से मेलामाईन के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की अधिसूचना संख्या 10/2010-सीमाशुल्क दिनांक 19.02.2010 को जारी की गई थी।
- 4. यत: मेसर्स गुजरात स्टेट फर्टीलाजर्स एंड केमिमकल्स लिमिटिड ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक विधिवत् पर्याप्त प्रमाणों से युक्त एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षित होने की संभावना का आरोप लगाया गया है तथा इसकी समीक्षा करने और मौजूदा पाटन-रोधी शुल्कों की अविध को आगे बढाने, उसमें संशोधन करने और उनकी राशि को बढाने का अनुरोध किया है।
- 5. यत: प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणयुक्त आवेदन पत्र को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (5) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता और इसकी जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त हो जाने पर पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को उससे क्षति होने की संभावना है, की समीक्षा करने के लिए दिनांक 09.12.2014 की अधिसूचना संख्या 15/17/2014-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी।

ख. क्रिया विधि

- 6. प्राधिकारी द्वारा जांच करने के संबंध में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है :
- (i) प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनसार 9 दिसंबर, 2014 की जांच की शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास और उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रेषित की थी। ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें तथा इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपने लिखित विचारों से प्राधिकारी को अवगत कराएं। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां, ज्ञात निर्यातकों/आयातकों की सूची के साथ संबद्ध देशों के दूतावास को भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि वे संबंद्ध देश के निर्यातकों/आयातकों को यह परामर्श दें कि वे इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अंतर अपने उत्तर प्राधिकारी को भेज दें।
- (ii) नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन के अगोपनीय वृतान्त की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों, अन्य घरेलू उत्पादकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई गई थी।
- (iii) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के बारे जारी की गई सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी थी और उन्हें अवसर प्रदान किया था कि वे नियमावली के अनुसार इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने लिखित विचार प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दें :-
 - (क) चाईना हुआया ग्रुप कंपनी लिमिटिड
 - (ख) जिंगकाऊ टिआन्यान इलेबोरेट केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटिड
 - (ग) इनर मंगोलिया ईहजुकेम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटिड

- (घ) नेईयार केमिकल कंपनी लिमिटिड
- (ङ) हेनेना हार्वेस्ट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटिड
- (च) हेनान होंगई केमिकल कंपनी लिमिटिड
- (छ) गोल्डन एलीफेंट केमिकल कंपनी लिमिटिड
- (iv) संबद्ध जांच शुरू होने के उत्तर में संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करके अपने उत्तर नहीं दिए हैं।
- (v) चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे (एमईटी) से संबंधित प्रशनावली इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी को संबद्ध सूचना प्रस्तुत कर दें। जबिक जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ चीन जनवादी गणराज्य में प्रचलित सामान्य मूल्य पर भारत में विधिवत समायोजित संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर विचार किया गया था, फिर भी प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को यह सूचित कर दिया था कि वे यथा संशोधित पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आलोक में आवेदन पत्र की दावे की जांच करेंगे। इसलिए चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों से अनुरोध किया गया था कि वे यथा उल्लिखित ऐसी आवश्यक सूचना/पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करें जिसके आधार पर प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकें कि क्या चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जा सकता है अथवा नहीं। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन जनवादी गणराज्य को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने का खंडन करने के आशय के एमईटी की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- (vi) नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के प्रयोजन से भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को प्रश्नाविलयां भेजी गईं थीं:-
 - (क) ग्रीनप्लाई लिमिटिड
 - (ख) मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटिड
 - (ग) मेरिनो मेनल प्रोडक्ट्स लिमिटिड
 - (घ) गोल्डन लेमिनेट्स लिमिटिड
 - (ङ) सूर्या विकास प्लाईवुड निजी लिमिटिड
 - (च) कात्यानी केमिटेक इंडिया लिमिटिड
 - (छ) रूशिल डेकर लिमिटिड
 - (ज) सनडेक इंडिया लिमिटिड
 - (झ) ब्लूम डेकर लिमिटिड
 - (অ) एचईएफ इंडिया प्राईवेट लिमिटिड
 - (ट) सेुचुरी प्लाईबोर्डस् इंडिया लिमिटिड
 - (ठ) मंगलम टिम्बर प्रोडकटस् लिमिटिड
 - (ड) वर्गों इंडस्ट्रीज
 - (ढ) अल्फा ईका लिमिटिड

- (ण) बम्बई वर्मा ट्रेडिंग कंपनी
- (vii) उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने मेसर्स अर्नेस्ट एंड जंग के माध्यम से प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :-
 - (क) मेघदूत लेमिनार्ट प्राईवेट लिमिटिड
 - (ख) सेंचुरी प्लाईबोर्डस् इंडिया लिमिटिड
 - (ग) ब्लूम डेकर लिमिटिड
- (viii) इसके अतिरिक्त लेमिनेट मेन्युफेक्चरर्स ऐसोसिएशन ने मेसर्ज अर्नेस्ट एंड जंग के माध्यम से याचिका का उत्तर प्रस्तुत किया है।
- (ix) मेसर्ज संदीप आर्गेनिक्स ने 28 जनवरी, 2015 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया था लेकिन उसने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उसने दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के ई मेल द्वारा और निवेदन प्रस्तुत किए थे। प्राधिकारी द्वारा मौखिक सुनवाई किए जाने के नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी कंपनी ने मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया था।
- (x) मैसर्स बालाजी एक्शन बिल्डबेल (आईटीएस कानूनी वकीलों और परामर्शदाताओं के माध्यम से) और मेसर्ज एक्जिम कोर्प ने निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत नहीं कराया है और न ही उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी आयातक प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत किया है, लेकिन उन्होंने विलंब से अक्टूबर, 2015 में अपने निवेदन प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार इन पक्षकारों ने उन्हें समय पर दिए गए अवसर का फायदा नहीं उठाया है। मेसर्ज बालाजी एक्शन बिल्डबेल ने सार्वजनिक फाईल को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं को पंजीकृत नहीं कराया है और उसने कोई निवदेन नहीं किया है/आयात के कोई आंकडे प्रस्तुत नहीं किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि पाटन-रोधी शुल्क की जांच समयबद्ध है, इसलिए पंजीकृत पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए और दर्ज किए गए निवेदनों का आदान-प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है, तािक प्राधिकारी को उचित निर्धारण करने में सहायता दी जा सके। मेसर्ज बालाजी एक्शन बिल्डबेल के मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी ने 10 महीनों तक इस जांच में कोई सहयोग नहीं दिया है और प्राधिकारी से जांच के केवल ग्याहरवें महीने में ही अनुरोध किया है, फिर भी प्राधिकारी ने व्यावहारित रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन को ध्यान में रखा जाए और उन पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाए।
- (xi) जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को अपने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं और न ही उन्हें इस जांच से संबद्ध कोई सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें असहयोगी माना गया है।
- (xii) जांच अवधि सिहत विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारोबार-वार आंकडे प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी प्रणाली, वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को उक्त सूचना प्राप्त हो गई है। प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने तथा क्षति का विश्लेषण करने के लिए डीजी प्रणालियों द्वारा प्रदत्त आंकडों पर विश्वास किया है जिनके कारणों का उल्लेख इस निर्णय में नीचे किया गया है।
- (xiii) सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की ईष्टतम लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) को

ज्ञात किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है।

- (xiv) मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2013 से 30 जून, 2014 (15 महीनों) तक की है। तथापि, क्षिति का विश्लेषण करने की अवधि में अप्रैल, 2010 मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 मार्च, 2013 और जांच अवधि भी शामिल है।
- (xv) पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 28 सितंबर, 2015 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें और साथ ही अपने प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत करें।
- (xvi) इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों की जांच की गई है और प्राधिकारी द्वारा जहां कहीं भी प्रासंगिक हुआ है, उनका निदान इस जांच में किया गया है।
- (xvii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकडों की जांच, जितनी आवश्यक समझी गई है, उतनी की गई है।
- (xviii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय वृतान्त भी प्रस्तुत करें।
- (xix) जहां कहीं भी यदि किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना का अभिगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध आंकडों के आधार पर उसे इस अंतिम निर्णय में उसको रिकार्ड किया है।
- (xx) उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2015 को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष अत्यावश्यक तथ्यों के विवरण का प्रकटन किया गया था और उस पर प्राप्त हुई टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया उतना इस अंतिम परिणाम में विचार किया गया है।
- (xxi) इस अंतिम परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार/अन्य पक्षकार द्वारा '' *** ''सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है ।
- (xxii) प्राधिकारी द्वारा इस जांच के लिए अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 60.64 रूपए है ।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का कार्य क्षेत्र</u>

7. मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद मेलामाईन है। मूल मामले में दिनांक 3 सितंबर, 2004 को अधिसूचना संख्या 14/16/2003-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद मेलामाईन है, जो कि स्वाद रहित, सुगंध रहित अवैषिक पदार्थ । इसका उपयोग मेलामाईन फोरमेल्डिहाईड के लिए किया जाता है, जिसका बाद में प्रयोग निचले स्तर के उत्पादों के लिए किया जाता है। मेलामाईन फोरमेल्डिहाईड रेसिन का प्रयोग परतदार बनाने के लिए किया जाता है जो कि सख्त, ख़ुचरन, दाग, धब्बे और ताप रोधी होता है।

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में मेलामाईन का कटिबद्ध सीमाशुल्क उप शीर्ष 29336100 है। ।यह उत्पाद ओजीएल श्रेणी में आता है और इसका आयात स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है "।

- 8. चूंकि मौजूदा जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही है जो कि मूल जांच में था। विचाराधीन उत्पाद मेलामाईन है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 में उप शीर्ष 29336100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से मौजूदा जांच के कार्य-क्षेत्र में बाध्यकारी नहीं है।
- 9. समान वस्तु के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में की गई व्यवस्था निम्नानुसार है :-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है, परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

- 10. प्रस्तुत किया गया आवेदन लागू किए गए पाटन-रोधी शुल्क की समीक्षा करने, जारी रखने और उसकी मात्रा को बढाने के लिए है तथा समान वस्तु जैसे मुद्दे का निदान विगत जांच में किया गया है। पहले की जांच में प्राधिकारी ने पहले से ही यह माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं चीन जनवादी गणराज्य से आयाति संबद्ध वस्तुओं के ही समान हैं।
- 11. विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेड के होने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक ने इस जांच में न तो कोई सहयोग दिया है और न ही विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों के बारे में कोई सुचना प्रस्तुत की है।
- 12. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित मेलामाईन और चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित मेलामाईन में विशेष अंतर व्याप्त है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित मेलामाईन और चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित मेलामाईन, उनकी वास्तविक और रसायनिक गुण-क्षमताओं, कार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देश्नों, कीमत, वितरण और विपणन की दृष्टि से तुलनीय है। हालांकि मेलामाईन के उत्पाद में विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाएं/प्रोद्योगिकीयां निहित हैं, फिर भी उसके अंत प्रयोग का तुलनीय विनिर्देशन है और उसे एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का प्रयोग, इनको पारस्परिक रूप से बदलने के लिए किया है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित मेलामाईन और चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित मेलामाईन को पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तु माना गया है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और आधार</u>

13. मेसर्ज गुजरात राज्य फर्टालाईजर्स एंड केमिकल्स लिमिटिड द्वारा आवेदन पत्र निर्णायक समीक्षा जांच के लिए प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकादाता कंपनी, संबद्ध देश के किसी निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से (न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से) कोई संबंध नहीं रखती है। याचिकादाता ने जांच अविध के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है। तथापि, याचिकादाता ने आधार वर्ष के दौरान संबद्ध देश से कुछ आयात किए थे। प्राधिकारी का यह विचार है कि कंपनी का मुख्य संकेन्द्रण निरंतर एक उत्पादक बने रहना और अपना निजी उत्पादन करना ही है। इसलिए कंपनी को नियमावली में दी गई परिभाषा के भीतर एक घरेलू उद्योग माना गया है।

14. याचिकादाता कंपनी भारत में विचाराधीन उत्पाद की एक मात्र उत्पादक है। प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना की जांच करने के बाद यह निर्धारित किया है कि याचिकादाता कंपनी नियम 2 (ख) में उल्लिखित व्यवस्था के भीतर एक घरेलू उद्योग बनती है और उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार घरेलू उद्योग के दर्जे के मानदंड को संतोषजनक ढंग से पूरा करती है।

ङ. <u>अन्य मुद्</u>दे

निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

- 15. निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-
 - (1) प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआईएस के आंकडों पर विश्वास किया है क्योंकि आंकडों के निजी स्नोत के बजाय यह एक सरकारी स्नोत है। हाल ही में संबंद्ध वस्तुओं के आयातों पर रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय की रिपोर्ट में डीजीसीआईएस के आंकडों की तुलना में आयात की कीमत काफी अधिक दर्शाई गई है।
 - (2) डीआरआई द्वारा जारी किए गए चेतावनी के एक परिपत्र से संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में यह बताया जाता है कि ऐसी चेतावनी क्षेत्रीय संगठन को ऐसी पद्धित से सचेत करना मात्र है, लेकिन यह संबद्ध वस्तुओं से संबंधित समस्त आयातों के कारोबार पर कोई आच्छादित और अंतिम जांच निर्णय नहीं है। यह कोई स्वीकारोक्ति भी नहीं है कि आयात की कीमतें मुख्यतया आयातकों द्वारा परिचालित की जाती हैं, लेकिन यह क्षेत्रीय संगठनों के लिए चेतावनी मात्र है कि पाटन-रोधी शुल्क से बचने के मकसद से आयात की कीमतों के संभावित परिचालन से सावधान रहें।
 - (3) आयात कारोबार की सत्यता, जो कि सीमाशुल्क विभाग के नियंत्रण और निगरानी का विषय है, अनावश्यक है। यदि सीमा शुल्क की क्रियाविधियों के बारे में, जो कि अवास्तविक आयात कारोबार को रोकने में विफल रही हैं, के तंत्र को चुनौती देने वाली कोई शिकायत की जानी है तो ऐसी शिकायत उपयुक्त मंच अर्थात, सीमाशुल्क विभाग के समक्ष ही की जाए। आयात के आंकडों की सत्यता को चुनौती देने और यह आरोपित करने के लिए कि आयात की कीमतें अवास्तविक हैं, जो कि डीजीसीआईएस के डाटाबेस अथवा सूचना पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, उन्हें प्राधिकारी द्वारा अनेक पाटन-रोधी जांच में सही और विश्वसनीय पाया गया है।
 - (4) जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना, विधिवत पर्याप्त प्रमाणयुक्त आवेदन पत्र पर आधारित नहीं है और नहीं यह प्रमाण की उचित और लक्ष्यपरक जांच पर आधारित है।
 - (5) आवेदक ने अपनी सूचना ऐसे प्रपत्र में अग्रेषित की है जो कि वास्तव में मूल आवेदन पत्र के निमित्त है और यह एसएसआर जांच के लिए नहीं है। इसके फलस्वरूप असंगत स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार की सूचना मूल जांच के लिए अपेक्षित होती है, वह विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं होती है जिसे प्राधिकारी द्वारा एसएसआर जांच के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है।
 - (6) जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना न तो यथापूर्व स्थिति के आधार पर है और न ही यह माननीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रमाण युक्त आवेदन पर आधारित है, जिससे कि मौजूदा जांच की शुरूआत यथोचित हो सके।
 - (7) विदेश ब्यापार नीति के अनुसार अग्रिम लाईसेंस /प्राधिकरण के अंतर्गत आयात, मानक इनपुट आउटपुट के मानदंडों द्वारा अधिशासित होते हैं।

- (8) यहां तक संबद्ध वस्तुओं का संबंध हैं, मांग और पूर्ति में अत्यधिक अंतर व्याप्त है। तथापि, अत्यधिक मांग होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग का यह दावा है कि उसके अपनी कीमते आयातित वस्तुओं के साथ जोडी हुई हैं। घरेलू उद्योग द्वारा अग्रिम लाईसेंस तंत्र के अंतर्गत ऐसे आयात किए गए हैं जो कि बिल्कुल भी भारतीय घरेलू बाजार में बिक्री के निमित्त नहीं होते हैं और न ही वे घरेलू बिक्रियों के साथ कोई प्रस्पिद्धी करने के लिए होते हैं।
- (9) ऐसा स्वीकार किया गया है कि एक- तिहाई आयात, शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत किए गए हैं, जिन पर पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगता है और दो-तिहाई आयात, उपरोक्त कीमत अर्थात अमरीकी डालर 1400 पर किए गए हैं। इस प्रकार इनका तात्पर्य यह है कि ये पाटित कीमतें हैं। यदि आयात की कीमतें अवास्तविक हैं, तो घरेलू उद्योग को मध्याविध समीक्षा करने को अनुरोध करना था।
- (10) शुल्क की कीमत के अप्रभावी होने के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को शुल्क की मात्रा और स्वरूप में परिवर्तन किए जाने के लिए मध्याविध समीक्षा करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। घरेलू उद्योग ने ऐसे दावे की संपुष्टि के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।
- (11) चीन के सीमा शुल्क के आंकडों में ऐसे कारोबार भी शामिल होंगे जो कि शुल्क-मुक्त तंत्र के अंतर्गत किए गए हैं, जिन पर पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगता है और इसलिए उन्हें पाटन और क्षित के विश्लेषण के परिवेश और अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए । जबिक क्षित का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ पहुंच मुल्य आवश्यक होगा जो कि प्रविष्टियों के आंकडों में पहले से ही उपलब्ध है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

- 16. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और उसके दर्जें के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-
 - (1) डीआरआई का निष्कर्ष प्रकृति स्वरूप निश्चायक है और निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सरकारी विभाग के निर्णयों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। डीआरआई की जांच के आधार पर सीमा शुल्क विभाग ने यह पाया था कि कुछ आयातक चीन से आयातित मेलामाईन का अधिक मूल्यांकन करने में संलिप्त थे तािक ऐसे आयातों पर प्रभारित पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करने से बचा जा सके। डीआरआई ने जांच करने के बाद अपने निष्कर्ष में यह निवेदन किया है कि आयातक पाटन-रोधी शुल्क का भुगतान करने से बचने के लिए उत्पाद का अधिक मूल्यांकन कर रहे हैं।
 - (2) घरेलू उद्योग ने डीआरआई के निष्कर्ष के लिए समर्थित प्रमाण सहित विस्तृत कारण दिए हैं ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि आयात के आंकडों में उल्लिखित कीमत अवास्तविक कीमत है और यह वास्तविक नहीं है।
 - (3) डीजीसीआईएंडएस की औसत आयात कीमत पर याचिका और लिखित निवेदनों में सुस्पष्ट किए गए कारणों के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
 - (4) याचिका में सकारातमक कीमत कटौती को स्पष्ट दर्शाया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में ऐसे विवरण निहित हैं जो कि घरेलू उद्योग की एक वर्ष के कार्य-निष्पादन में गिरावट दर्शाते हैं। तथापि, वार्षिक रिपोर्ट केवल विचाराधीन अवधि पर ही ध्यान संकेन्द्रित करती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए केवल क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन ही महत्व रखता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का निर्णय क्षति अवधि के दौरान हए कार्य-निष्पादन पर आधारित है।
 - (5) अग्रिम लाईसेंस के अंतर्गत होने वाले आयात घरेलू उद्योग को क्षिति पहुंचा रहे हैं। अग्रिम लाईसेंस के अंतर्गत भारत में प्रवेश करने वाले आयात ऐसे आयात हैं जो कि घरेलू उद्योग की कीमत और समग्र बाजार की कीमत को अधिशासित कर रहे हैं। भारत सरकार ने निर्यात के लिए किए जाने वाले आयात को अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत पाटन-रोधी शुल्क के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह

- नहीं है कि ऐसे आयात क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। इससे पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के समय भारत सरकार के विवेकाधिकार का ही स्पष्ट पता चलता है।
- (6) घरेलू उद्योग ने ऐसे विस्तृत कारण प्रस्तुत किए हैं कि श्रेणी 1 अथवा चीन सीमाशुल्क आंकडों के तहत होने वाले आयातों को ही घरेलू आयात कीमत का निर्धारण करने के लिए क्यों अपनाया जाए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 17. प्राधिकारी भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की वास्तविक कीमत पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट करते हैं। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि भारतीय सीमा शुल्क के अनुसार आयात की कीमत, वास्तविक कीमत नहीं है और इसलिए यह अनुरोध किया है कि या तो चीन के सीमा शुल्क के अनुसार कीमत को अथवा अग्रिम लाईसेंस के अंतर्गत आयातों की कीमत को अपनाया जाए। घरेलू उद्योग ने अपने इस तर्क के समर्थन में डीआरआई द्वारा परिचालित एक चेतावनी परिपत्र प्रदान किया है जिसमें डीआरआई ने यह पाया है कि व्यापारी आयातक, वास्तविक प्रयोक्ता आयातक के आयात मूल्य की तुलना में अत्यधिक मूल्य घोषित कर रहे थे। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार का यह तर्क है कि डीआरआई का चेतावनी संबंधी पत्र क्षेत्रीय संगठनों को ऐसी पद्धित से सचेत करना मात्र है, लेकिन यह संबद्ध वस्तुओं से संबंधित समस्त आयातों के कारोबार पर कोई आच्छादित और अंतिम जांच निर्णय नहीं है तथा ऐसे आयात के कारोबार की सत्यता जो कि सीमा शुल्क के नियंत्रण और निगरानी के अध्यधीन होते हैं, अनावश्यक है तथा प्राधिकारी द्वारा आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकडों को ही अपनाया जाना चाहिए।
- 18. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को केवल डीजीसीआईएंडएस के आंकडों पर ही विश्वास करना चाहिए तथा निजी स्रोत अथवा किसी अन्य स्रोत पर नहीं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत में उसने आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए आंकडों की प्रकृति, उसकी उपलब्धता, परिप्रेक्ष्य और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए तथ्यों के उपयुक्त सह-संबंध के बाद ही निजी स्रोत के आंकडों के साथ-साथ चीन के सीमाशुल्क के आंकडों को अपनाया था। जांच की शुरुआत करने के समय आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए आईबीआईएस के आंकडों को अपनाया जाना भी निर्दिष्ट प्राधिकारी की विगत की पद्धति रही है।
- 19. आयात कीमत का निर्धारण करने के संबंध में प्राधिकारी ने डीआरआई द्वारा की गई जांच के ब्यौरों तथा उनके द्वारा निर्धारित आयातों के वास्तविक मूल्य के संबंध में डीआरआई से सूचना के अनुरोध को नोट कर लिया है, तािक पाटन और कीमत के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके।
- 20. इसलिए प्राधिकारी विचाराधीन उत्पादों के आयातों की मात्रा और कीमत के लिए आयात के आंकडों के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट करते हुए यह मानते हैं कि विगत में उसने आंकडों के विभिन्न स्रोतों का आंकडों के स्रोत में उपलब्ध आंकडों के ब्यौरों की सीमा तक उपयुक्त ढंग से उपयोग किया था, उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जितना संभव था उतना उन पर विश्वास किया था और विभिन्न स्रोतों तथा साथ ही सहयोगी निर्यातक/आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के बीच पारस्परिक संबंध होने के लिए विभिन्न द्वितीयक स्रोतों के आंकडों के सही होने की सुनिश्चितता की है। मौजूदा मामले में प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के साथ-साथ डीजी प्रणाली के आंकडों पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने डीआरआई द्वारा जारी किए गए चेतावनी परिपत्र पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर कुछ व्यापारियों/आयातकों द्वारा पाटन-रोधी शुल्क के आरोपित प्रवंचना करने पर डीआरआई से संबद्ध ब्यौरे भी प्राप्त किए हैं। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस, डीजी प्रणाली और चीन सीमाशुल्क से प्राप्त आंकडों और डीआरआई से प्राप्त सूचना के बीच सह-संबंध स्थापित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस, डीजी प्रणाली और चीन सीमाशुल्क के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा मोटे तौर पर सह-संबंधित है। चूंकि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं प्रस्तुत किया है तथा केवल तीन निर्यातकों ने ही ***मी.टन के आयातों के आंकडे प्रस्तुत किए हैं, इसलिए आयातक की प्रश्नावली के उत्तर के

अनुसार कीमत, विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों से प्रतिबिम्बित नहीं हो सकती है। डीजी प्रणाली के आंकडों के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क मुक्त आयातों और गैर-शुल्क मुक्त आयातों के बीच व्यापक अंतर विद्यमान है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि उत्पाद का आयात, दोनों मार्गों में समान है। डीआरआई को चेतावनी परिपत्र और डीआरआई द्वारा प्राधिकारी को प्रदत्त सूचना इसके प्रमाण हैं कि जब जांच अविध के दौरान गैर-शुल्क मुक्त आयातों की आयात कीमत की तुलना, अग्निम लाईसेंस की कीमतों से की जाती है तो वह विश्वसनीय नहीं होती है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने चीन सीमाशुल्क के आंकडों और डीजी प्रणाली के अनुसार शुल्क मुक्त आयातों की आयात कीमत के अनुसार समग्र आयात कीमत की जांच की है और यह पाया है कि मोटे तौर पर ये कीमतें सह-संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त डीआरआई द्वारा की गई जांच भी इन दोनों कीमतों की विश्वसनीयता की भी संपृष्टि करती है। इसलिए प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि पाटन और क्षित दोनों का निर्धारण करने के लिए डीजी प्रणाली के आंकडों के अनुसार शुल्क मुक्त आयातों की आयात कीमत को अपनाना उचित और उपयुक्त है।

- 21. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 (1ख) के अनुसार पर्याप्त और सही सूचना प्रस्तुत करके "विधिवत् पर्याप्त प्रमाण युक्त" आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण के आधार पर शुरू की गई थी जो कि पाटन, क्षिति और कारणात्मक संबंधों को दर्शाते हैं तथा उक्त पाटन-रोधी शुल्क की समाप्ति के फलस्वरूप पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षिति होने की संभावना रहती तथा यह अधिनियम और नियमावली के अनुसार ऐसी जांच की शुरुआत करने को यथोचित ठहराते हैं। इस चरण में उपलब्ध आंकडे, जांच शुरू करने के समय अपनाए गए उपागम की परिपृष्टि करते हैं।
- 22. पाटन और क्षति का निर्धारण करने के लिए अग्रिम लाईसेंस के अंतर्गत आयात को बाहर रखने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इन आयातों को पाटन और क्षति का आकलन करने के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया था क्योंकि ऐसे पाटित आयात घरेलू उद्योग को इन निर्यातकों की अपनी आपूर्तियां बढाने और उस सीमा तक बढाने के लिए जिससे कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट हो, उपलब्ध होने वाले अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते थे। यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी की ऐसी सुसंगत पद्धित रही है कि वे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ शुल्क मुक्त व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले आयातों को शामिल करें।
- 23. शुल्क के स्वरूप और आरोपित अधिक बीजक बनाने के संबंध में प्राधिकारी ने उपयुक्त रूप से उपाय करने का निर्णय लेने के लिए मौजूदा मामले में तथ्यों पर विचार किया है।

ङ. <u>बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

निर्यातकों, आयातकों तथा हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

- 24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निर्यातकों, आयातकों तथा हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-
 - (1) भारत चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि देश नहीं माना जा सकता है क्योंिक (क) चीन में उत्पादकों के प्रचालन की मात्रा भारत में उत्पादकों की तुलना में बहुत अधिक है, (ख) चीन में विनिर्माताओं की उत्पादन की क्षमताएं आवेदक की क्षमताओं से बहुत अधिक है, (ग) अर्थव्यवस्था बनाए रखने के फलस्वरूप चीन में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत, भारत में उत्पादन लागत से काफी कम है तथा (घ) चीन अपनी मेलामाईन का उत्पादन, कोयले की गैस का प्रयोग करके करता है जो कि भारत में प्रयुक्त होने वाले यूरिया की तुलना में सस्ती और अधिक कारगर होती है।

- (2) सामान्य मूल्य की संरचना की अनुमित नहीं है और निर्यात मूल्य को परिकलन सही नहीं किया गया है, प्राधिकारी को डीआई द्वारा परिकलित पाटन मार्जिन के परिणाम की अनदेखी करनी चाहिए।
- (3) उर्वरकों से अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए एपीएम कीमतों पर अधिप्राप्त की गई प्राकृतिक गैस प्रयुक्त करने के लिए आवेदक के खिलाफ अनेक न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन हैं । विशेषकर मेलामाईन जैसे उत्पादों के उत्पादन के लिए एपीएम कीमतों पर अधिप्राप्त की गई प्राकृतिक गैस को अवैध रूप से प्रयुक्त करने से संबंधित कार्यवाहियां । सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए आवेदक के आंकडों का प्रयोग करना उपयुक्त अथवा उचित नहीं है ।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

- 25. घरेलू बाजार के कार्य-क्षेत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-
 - (1) चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। विगत में यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका ने उसे ऐसा ही माना है। क्रियाविधि का व्यापक मूल्यांकन और जांच करने के बाद किसी भी देश ने चीन को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा नहीं दिया है। भारत में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 31 मई, 2002 के संशोधन के बाद शुरू की गई सभी जांच में व्यावहारिक रूप से चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश ही माना है।
 - (2) पाटन-रोधी नियमावली ने कुछ शर्ते निर्धारित की हैं जिन्हें बाजार-अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के लिए संतोष जनक ढंग से पूरा करना होता है । बाजार-अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए इच्छुक निर्यातक को ऐसी प्रत्येक शर्त को पूरा करना अपेक्षित होता है ।
 - (3) मौजूदा मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण, कीमत के आधार पर अथवा तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था में संचरित मूल्य के आधार पर इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि संबद्ध सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
 - (4) घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए आईबीआईएस के आंकडों पर विश्वास किया है। तथापि, आईबीआईएस अभिगम मूल्य के रूप में आयात मूल्य प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन के पाटन-रोधी संबंधी करार और भारतीय नियमावली के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना व्यापार के समान स्तर पर ही की जानी चाहिए। इसलिए निर्यात कीमत को समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बन्दरगाह के खर्चों, बैंक प्रभारों, अंतर्देशीय भाड़े के व्यय और वीएटी समायोजन के लिए समंजित किया गया है।
 - (5) पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और यह विद्यमान शुल्कों के बावजूद बहुत अधिक है।
 - (6) घरेलू उद्योग के स्व:व्यवस्थित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुमानित सामान्य मूल्य कृत्रिम रूप से ऊपर रखा गया है ताकि पाटन रोधी व्यवस्था से प्राप्त होने वाले लाभ को किसी तरह से निरंतर प्राप्त किया जाता रहे ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 26. धारा 9 क (1) (ग) के अंतर्गत समान वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य यह है कि -
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेत् उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

- 27. जांच शुरू किए जाने के चरण में प्राधिकारी ने इस पूर्वधारणा से कार्रवाई शुरू की थी कि चीन जनवादी गणराज्य एक गैर-अर्थव्यवस्था वाला देश है। जांच शुरू करने पर प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी थी कि वे जांच शुरू करने के नोटिस का उत्तर दें तथा अपनी बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का निर्धारण करने से संबद्ध सूचना प्रस्तुत करें । प्राधिकारी ने एमईटी के प्रश्नावली की प्रतियां सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी थीं कि वे नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में निर्धारित मानदंड के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की पूर्वधारणा का खंडन करने के लिए अपने उत्तर प्रस्तुत करें । प्राधिकारी ने चीन सरकार से भी अनुरोध किया था कि वह अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध सूचना प्रेषित करने की सलाह दें । तथापि, चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- 28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में चीन जनवादी गणराज्य को भारत और विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा पाटन-रोधी जांच में एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। चीन जनवादी गणराज्य को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है, जब तक कि नियमावली के अनुसार निर्यातक देश अथवा पृथक विशिष्ट निर्यातक द्वारा ऐसी पूर्व अवधारणा का खंडन नहीं कर दिया जाता है।
- 29. पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, के अनुबंध-क के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है, यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है । चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तािक निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जा सकें कि क्या :-
 - (क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;
 - (ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;

- (ग) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- (घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जांच शुरू करने के नोटिस के फलस्वरूप किसी भी चीन की कंपनी ने निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए है। इसलिए प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध-। का पैरा 8 चीन की कंपनियों के लिए लागू करने की स्थिति में नहीं है और नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार आगे बढ़ गया है। इन नियमावली के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है:

- क. किसी तीसरे देश बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत के आधार पर, अथवा
- ख. किसी तीसरे देश बाजार अर्थव्यवस्था में संरचित मूल्य, अथवा
- ग. ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए भारत सहित कीमत।
- घ. यदि उपर्युक्त वैकल्पिकों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी औचित्यपूर्ण लाभ मार्जिन सहित विधिवत रूप से समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य औचित्यपूर्ण आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।
- 31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देश लागत और कीमतों पर आधारित सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री अथवा उत्पादन की लागत के साथ-साथ अन्य देश निर्यात बिक्री के संपूर्ण और विस्तृत आंकड़े तथा अन्य देशों में इस प्रकार के उत्पादकों का सहयोग अपेक्षित है। चूंकि इन मामलों में प्रचलित कीमत और लागतों के संबंध में किसी सूचना का मूल्यांकन नहीं किया जा सका और विरोधी हितबद्ध पक्षों को भी उपयुक्त अन्य देश बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में कोई दूसरे परंतुक की शर्तों के अनुसार अन्य औचित्य आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में सामान्य मूल्य निकाला गया है। इस प्रकार प्राधिकारी चीन से जांच अविध के दौरान विचाराधीन आयातित उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य संरचित करने के लिए निम्नानुसार निर्धारित करता है:-
 - (क) उपलब्ध बेहतर सूचना के आधार पर कच्चे माल के बेहतर उपयोग मानदण्ड माने गए हैं।
 - (ख) उपयोगिता की लागत, परिवर्तन लागत, एसजीए व्यय और ब्याज बेहतर उपलब्ध सूचना के आधार पर माना गया है।
 - (ग) ब्याज को छोड़कर बिक्री की लागत के 5% के औचित्यपूर्ण लाभ के रूप में अनुमति दी गई है।
- 32. तदनुसार कारखाना बाह्य स्तर पर संगणित संरचित सामान्य मूल्य *** अमरीकी डॉलर प्रति एमटी (रूपए***प्रति एमटी) निर्धारित किया गया है।

संबद्ध देश की निर्यात कीमत

33. चूंकि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जो निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए प्रयोग की जा सके। इसलिए प्राधिकारी चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों की निर्यात कीमतों के साथ विधिवत रूप से सहसंबद्ध डीजी प्रणाली आकड़ों के अनुसार भारत में शुल्क मुक्त आयात की सीआईएफ कीमत के आधार पर संबद्ध देश से सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमतें निर्धारित करने का मत रखता है। प्राधिकारी यह दृष्टिकोण अपनाते समय गैर-अग्निम लाइसेंस आयात के तहत पाटनरोधी शुल्क के धोखेबाजी की डीआरआई जांच के परिणामों और चीन पीआर से पीयूसी के व्यापारियों/ आयातकर्ताओं द्वारा कीमत

प्रकटीकरण तथा उनके द्वारा एडीडी के स्वैच्छिक निक्षेपण जो अविश्सनीय रूप से गैर-शुल्क मुक्त रूट के अंतर्गत पीयूसी की आयात कीमतें प्रदान करता है, को ध्यान में रखता है।

34. तदनुसार चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात कीमत समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, अंतर्देशीय परिवहन और बैंक प्रभारों के लिए लागू समायोजन से उपरोक्त पैरा 33 में उल्लिखित उत्पाद की सीआईएफ कीमतों के आधार पर गणना की गई है और कारखाना बाह्य निर्यात कीमतें निकाली गई है। तदनुसार निवल निर्यात कीमत अमेरिकी डॉलर***प्रति एमटी (रूपए***प्रति एमटी) निर्धारित की गई है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

35. उपरोक्त निर्धारित अनुसार सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमतों को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं।

विवरण	इकाई	चीन जनवादी गणराज्य (पीओआई)
संचरित सामान्य मूल्य	अमेरिकी डॉलर/एमटी	***
निवल निर्यात मूल्य	अमेरिकी डॉलर/एमटी	***
पाटन मार्जिन	अमेरिकी डॉलर/एमटी	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	% रेंज	40%-50%

36. उपरोक्त मूल्यांकन दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर चीन जनवादी गणराज्य से भारतीय बाजार में प्रवेश करती रही है और पाटन का मार्जिन पर्याप्त है।

छ. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति एवं आकस्मिक कारक की जांच

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों/अन्य पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

- 37. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों/अन्य पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :
 - I. 2010-11 की तुलना में पीओआई के दौरान आवेदक के उत्पादन में 7% तक वृद्धि हुई है। क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में कमी नहीं हुई है। क्षमता उपयोग विशेष रूप से आधार वर्ष की तुलना में और तत्काल पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाता है।
 - II. कोई कंपनी जो कथित रूप से क्षित वहन कर रही है, अपनी क्षमता में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं होगी। इसलिए उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और मालसूची से संबंधित आंकड़े आवेदक को हुई किसी क्षिति को नहीं दर्शाते।
 - III. जांच अवधि के दौरान डीआई की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है जो 15.3% की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त बिक्री मात्रा में भी वृद्धि हुई है।
 - IV. बाजार हिस्से में कमी इस तथ्य के कारण है कि अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए समान उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसके पास क्षमता नहीं है। घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में विफल रहा है,

- समान उत्पाद के घरेलू प्रयोक्ता आयात से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य किए गए। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी के लिए संबद्ध देश से आयात करने का दोष आवेदक पर लगाना अत्यधिक औचित्यपूर्ण नहीं है।
- V. डीआई मालसूची के कम स्तर को बनाए रखने में सक्षम रहा है। वास्तविकता यह है कि मालसूची में वृद्धि नहीं हुई है और अपेक्षाकृत जांच अवधि में गिरावट आई है।
- VI. यदि पाटन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाता है तो रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी निश्चित रूप से प्रभावित होगी। मजदूरी क्षति अविध के प्रत्येक वर्ष और जांच अविध के दौरान निरंतर बढ़ी है। इसके अतिरिक्त क्षति जांच अविध के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई है। यदि आवेदक वास्तव में क्षति वहन कर रहा होता तो कर्मचारियों की वृद्धि करने का कोई कारण नहीं होता और इसके अलावा अतिरिक्त कर्मचारी भाड़े पर लेता रहा। इसके विपरीत वह उद्योग जो क्षति वहन कर रहा है अथवा जिसको क्षति की आशंका है, की मजदूरी कम करने और/अथवा डाउनसाइज किए जाने की संभावना होती। उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।
- VII. डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों के अनुसार कोई कम दाम कीमत नहीं है। 52वीं वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 23 के अनुसार आवेदक की कुल मेलामाइन बिक्री वर्ष 2013-14 के लिए 13,920.61 लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त 52वीं वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 23 के अनुसार आवेदक ने 2013-14 के दौरान समान उत्पाद की 15,378 एमटी बिक्री की। इस प्रकार समान उत्पाद की यूनिट विक्रय कीमत 90,520 रुपए प्रति एमटी निकलती है। कम दाम कीमत जो डीजीसीआईएंडएस के अयात आकड़ों पर आधारित है, से संबंधित उपरोक्त गणना पर विचार करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध है।
- VIII. अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने के लिए बुनियादी कारण भारत से निर्यात को बढ़ावा देना है और इसलिए अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत शामिल कोई भी आयात अनिवार्यतः घरेलू उद्योग के लिए कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार कम दाम कीमत की गणना करने के प्रयोजन से अग्रिम लाइसेंस के तहत विचाराधीन उत्पाद के आयात पर विचार करना पूर्णतः गलत है।
- IX. विक्रय कीमत के साथ-साथ विक्रय की लागत में वृद्धि हुई है। बिक्री की लागत में वृद्धि होने से सबंद्ध वस्तुओं की विक्रय कीमत में वृद्धि हुई। 2013-14, 2012-13 और 2011-12 के लिए डीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि हो रही है। समान उत्पाद की बिक्री कीमत में निरंतर वृद्धि किसी आधारपर नकारी नहीं जा सकती जैसा कि आवेदक की आवदेक की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों से पूर्णतः सिद्ध है।
- X. संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 29% तक बढ़ी है। पीओआई में चीन से आयात का पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत से 7% अधिक था।
- XI. आवेदक की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है और कोई कीमत कटौती नहीं हुई है। इसलिए संबद्ध देशों से आयात ने क्षिति वहन किए जाने में कोई योगदान नहीं किया है। आवेदक द्वारा वहन की गई कोई भी क्षित कितपय असाधारण व्यय द्वारा ही स्पष्ट की जा सकती है।
- XII. 2013-14 के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में यह व्यवस्था है कि आयातित कच्ची सामग्रियों अर्थात अमोनिया और मध्य-पूर्व देशों और अफ्रीकी देशों से जहां राजनैतिक अस्थिरता ने आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित की थी, पर निर्भरता अधिक रही है और एक सीमा तक जीएसएफसी का उत्पादन और लाभप्रदता प्रभावित की है। इसके अतिरिक्त अमरीकी डालर की तुलना में रूपए के मूल्य हास ने उर्वरकों की उत्पादन लागत और आयात में वृद्धि की है। आवेदक के व्यय जैसे विद्युत और ईंधन, मूल्यहास, मजदूरी, वित्त लागत और अन्य व्यय क्षति अविध के दौरान काफी बढ़ गए हैं। आवेदक को अन्य व्यय मूल्यहास और मजदूरी जैसे व्यय में पर्याप्त वृद्धि के कारण वहन की गई

- होती तो निवेश पर प्रतिफल में गिरावट अथवा अर्जित लाभ और कोई हानि (निवल लाभ) निश्चित रूप से हो सकता था।
- XIII. चूंकि कोई मौजूदा क्षति नहीं है इसलिए डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 11.3 और भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1बी) के तहत क्षति के जारी रहने की संभावना है इसलिए वर्तमान जांच रूल आउट की गई है और इससे संगत नहीं है।
- XIV. भारत चीन से निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार नहीं है। विशेष रूप से चीन से भारत को संबद्ध वस्तुओं का कुल निर्यात केवल 11.3% है। भारत को निर्यात अपेक्षाकृत घटा है। चीन से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि चीन के निर्यातकों की क्षमताओं का ध्यान रखे बिना है। चीन के निर्यातकों की कुल क्षमताओं से संबंधित आंकड़े चीन के बाजार के लिए इसकी उत्पादन क्षमता के साथ-साथ संपूर्ण विश्व के बाजारों से संबंधित है।
- XV. अधिक क्षमताओं का अस्तित्व अपने आप में यह नहीं दर्शाता कि पाटन की संभावना है अथवा नहीं। वास्तविकता यह है कि चीन में काफी क्षमताओं का अस्तित्व भारत में पाटन की संभावना विशेष रूप से साक्ष्य यह प्रदर्शित करते हैं कि चीन से निर्यात अन्य बाजारों के लिए है जहां निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है और भारत को निर्यात अपेक्षाकृत घटा है।
- XVI. दस वर्षों के लिए शुल्क लगाए जाने के बाद भी निष्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह स्पष्ट है कि डीआई को निर्दिष्ट क्षति हुई है जो इसकी अपनी किमयों के परिणामस्वरूप हैं। सच यह है कि इसके लाभ और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट के कारण व्यय के परिणामस्वरूप और केवल डीआई के लिए मूलभूत है।
- XVII. आवेदक का वर्तमान धनात्मक निष्पादन, सभी महत्वपूर्ण क्षति मापदंडों के सुधार से प्रमाणित होता है, जो इसके अपने कार्यनीतिक निर्णय जैसे पूंजीगत निवेशों और क्षमता में वृद्धि से हुआ है।
- XVIII. निरंतर क्षति के बावजूद घरेलू उद्योग ने केवल अभी विस्तार करने के बारे में सोचा है और उसने लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन और वृद्धि करने के लिए कभी भी मध्यावधि समीक्षा आवेदन भेजा है।
 - XIX. आयात अनिवार्य रूप से भारी मांग और आपूर्ति अंतर के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। निःसंदेह आयातित वस्तुएं अपाटित कीमतों पर आनी चाहिए। यदि एक बार हम लेन-देन जो शुल्क-मुक्त तंत्र के तहत हुए हैं, को छोड़ देते हैं तो वर्तमान मामले में उपयुक्त ढंग से हुआ है।
 - XX. आवेदक यह 'सकारात्मक साक्ष्य' उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और परिणाम स्वरूप क्षति संभाव्य होगी।
 - XXI. यह कि क्षिति मार्जिन उन सौदों जो शुल्क मुक्त योजनाओं के तहत नहीं किए गए हैं, के लिए ही पहुंच मूल्य का ध्यान में रखते हुए माननीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जब वस्तुओं के लिए स्वीकृति दी गई है, उस समय की परिवर्तन दर (डालर का भारतीय रूपए में) को भी अनिवार्यतः ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- XXII. आवेदक वास्तव में लंबे समय (10 वर्षों के लिए) के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की निरंतरता के कारण उन्हें प्रोद्भूत लाभ अर्जित किए हैं और अब पुनः आगे और पांच वर्ष की अविध के लिए जारी रखने की अनुमित मांगी गई है। पाटनरोधी शुल्क अनिवार्यतः जारी नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत ने दस वर्ष की अविध के बाद उपायों को नहीं बढ़ाने के लिए डब्ल्यूटीओ के सामने अपना सिद्धांततः पक्ष रखा है।
- XXIII. मैसर्स जीएसएफसी की क्षमता 15000 टन वार्षिक है तथा वृद्धि के लिए योजना बनाई है।
- XXIV. यह तकनीकी प्रौद्योगिकी के साथ प्रौद्योगिकी चयन प्रक्रिया पर व्यय कर रहा है।
- XXV. विद्युत की खपत में वृद्धि हुई है जबिक वाष्प और गैस की खपत में कमी हुई है।

- XXVI. व्यापार में उत्पादन, बिक्री और स्टॉक में वृद्धि हुई है जबिक मालसूची में कमी हुई है। व्यापार में 2013 में 1179.11 लाख रुपए से बढ़कर 2014 में 2010.08 लाख रुपए हो गया है। अर्जित विदेशी मुद्रा वर्ष 2013-14 में 15.18 लाख रुपए है।
- XXVII. क्वालिटी में अंतर है। चीन की सामग्री में नाइट्रोजन और कोयला कच्ची सामग्री है।
- XXVIII. जीएसएफसी मेलामाइन का आयात और व्यापार कर रहा है।
 - XXIX. क्वालिटी के संबंध में काफी ग्रेड हैं।
 - XXX. जीएसएफसी एक सरकारी आधार वाली कंपनी है और एकाधिकार की स्थिति के अधिकार का भी प्रयोग करती है। जीएसएफसी में 12.36 शुल्क है। जीएसएफसी में बंदी तथा जीएसएफसी की क्षमता, मांग और आपूर्ति और यह तथ्य कि जीएसएफसी में हाल ही में नया प्रबंधन आया है, को ध्यान में रखते हुए डीजीएडी से अनुरोध किया गया है।
 - XXXI. सभी पक्षों द्वारा किए गए गैर-गोपनीय वर्जन अनुरोधों में यह सिद्ध करने के लिए मैसर्स संदीप ऑरगेनिक्स द्वारा डीजीएडी से अनुरोध किया गया है अन्यथा यह आरटीआई फाइल दायर करेगी अथवा प्रतिस्पर्धा आयोग में जाएगी अथवा उपयुक्त न्यायालय में रिट दायर करेगी।
- XXXII. अंतिम जांच परिणामों से पूर्व मौखिक साक्ष्य के लिए तथा प्रारंभिक विकर्ष परिणाम जारी करने के लिए भी डीजीएडी को अनुरोध किया गया है।
- XXXIII. पहुंच लागत का शुल्क 1%, 2% उपकर, 1% उपकर, 7.5% मूल शुल्क 12%, सीमा शुल्क और 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क है।
- XXXIV. यह आउटस्टेशन बिक्री के लिए 2% एसटी और मालभाड़ा प्रभारित करता है जिसमें क्रेता के लिए लागत बढ़ जाती है, किंतु आयात में कोई सीएसटी और मालभाड़ा नहीं है।
- XXXV. यह क्रेताओं को क्रेडिट नहीं देता और एजेंटों को कमीशन और प्रोत्साहन देता है।
- XXXVI. पिछले 11 वर्षों से पहले ही पाटनरोधी शुल्क है और वहीं लचीला पाटनरोधी शुल्क जारी रहना चाहिए।
- XXXVII. प्रकटन विवरण मैसर्स संदीप ऑरगेनिक्स को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और प्रारंभिक जांच परिणाम अंतिम विकर्ष परिणामों से पूर्व जारी किए जाने चाहिए।
- XXXVIII. आईसीआईएस रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक प्राइवेट और वाणिज्यिक रिपोर्ट है।
- XXXIX. चीन के निर्यात आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और भारतीय आयात आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए।
 - XL. कच्ची सामग्री अमोनिया, कोयला, यूरिया, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों के साथ-साथ वुड पैनल तथा एडहेसिव में उतार-चढ़ाव पर विचार किया जाना चाहिए।
 - XLI. अपरिष्कृत एवं मुद्रा (यूएसडी-आईएनआर तथा आरएमबी-आईएनआर) में उतार चढ़ाव पर विचार किया जाना चाहिए।
 - XLII. डीआरआई जांच निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है;
 - XLIII. अन्य देशों से आयात पर पाटनरोधी शुल्क है;

- XLIV. चीन की काफी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं।
- XLV. चीन की क्वालिटी बहुत घटिया है;
- XLVI. हाल ही में आयात में कमी हुई है और घरेलू उद्योग ने कीमतें बढ़ा दी है।
- XLVII. घरेलू उद्योग बार-बार बंदी की समस्या झेल रहा है और आयात एवं व्यापार कर रहा है।
- XLVIII. घरेलू उद्योग सरकारी नियंत्रण में है और आर्थिक सहायता प्राप्त करता है। यह व्यावसायिक रूप से प्रबंधित नहीं है और आयात के अस्पष्ट कारण देता है। इसके द्वारा साधनों का गैर पूंजीकरण किया गया है।
- XLIX. यह कच्चे माल और विद्युत की समस्याओं का सामना करता है और मशीनें भी पुरानी हैं।
 - L. डीएफआईए के अंतर्गत अब आयात भी रोक दिया गया है और आयात करना व्यवहार्य नहीं रहा;
 - LI. सीमा शुल्क एडीडी का भुगतान करने के पश्चात चीन के कार्गों को पास करता है;
 - LII. आयात पर 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क है और घरेलू उद्योग में 2% केंद्रीय बिक्री कर है।
 - LIII. कोई घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि मैसर्स जीएसएफसी लिमिटेड, आयातक संबद्ध सामान के उत्पादक का एकमात्र घरेलू उत्पादक है।
 - LIV. डीजीएडी द्वारा पद्धित का पालन किया जा रहा है जबिक अनुशंसित शुल्क तालिका दोषपूर्ण है क्योंकि एनआईपी को यूएस डॉलर में परिवर्तित करने पर घरेलू उद्योग के लाभ में कमी होने के कारण गंभीर समस्या है।
 - LV. बाजार अर्थव्यवस्था निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क की मात्रा शामिल समुद्री मालभाड़ा राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि निर्यातक के लिए कोई संरचित लागत अवधारणाओं में से एक दोषपूर्ण है, जिसे वैधीकृत नहीं किया गया है।
 - LVI. जबिक घरेलू उत्पादों के बहुत से ग्रेड हैं, भारित औसत बिक्री वसूली उचित नहीं है। घरेलू ग्रेडों को उचित तुलना करने के लिए आयातित मैलामाइन के संगत ग्रेडों के अनुरूप कोरिलेट किया जाना चाहिए
- LVII. पाटन के अलावा अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति की मात्रा निकाली जानी चाहिए और किसी उचित तुलना पर पहुंचने से पूर्व उसे पृथक किया जाना चाहिए।
- LVIII. पाटित कीमतों पर भारत में बेचे नहीं गए पाटित आयात की स्थिति विद्यमान है। डीजीएडी के पास पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए इस प्रकार के पाटित आयात को बाहर करने की पद्धित नहीं है। यह एडीए और पाटनरोधी नियमावली के तहत प्रतिबंधों और निषेधों का उल्लंघन है।

घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए

- 38. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए:
- i पूरी क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन वस्तुओं की प्रत्यक्ष खपत बढ़ी है। वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष से घरेलू उद्योग के बाजार शेयर में मामूली वृद्धि हुई है उसके बाद इसमें गिरावट आई है। चीन से आयात के बाजारी हिस्से में पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ii पाटन रोधी ड्यूटी के पूरी तरह से मौजूद होने के बावजूद भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- iii आयातों से घरेलू उद्योग कीमतों में कमी आ रही है।
- iv आयात से घरेलू कीमतें दबती जा रही है।

- v मुनाफा, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू उद्योग का निष्पादन बदतर हुआ है। पाटन के परिणामी प्रभाव ने घरेलू उद्योग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- vi पाटन रोधी ड्यूटी के अस्तित्व में होने के बावजूद लगातार पाटन और ड्यूटी के प्रकार के कारण घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानि हुई। उल्लेखनीय मात्रा में पाटित आयात के भारतीय बाजार में प्रवेश के कारण घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहने के लिए अपने माल को उप-इष्टतम मूल्य पर बेचना पड़ा। घरेलू उद्योग को लागत के अनुपात में कीमत बढ़ाने से रोक दिया गया।
- vii देश में मैलामाइन की मांग और पूर्ति में अंतर को देखते हुए याचिकाकर्ता विस्तार संबंधी कार्रवाई में संलग्न है जिसमें कंपनी की योजना अपनी क्षमता का विस्तार कर आगे 40,000 एमटी करना है। तथापि, उल्लेखनीय पाटन तथा इसके परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को होने वाली हानि को देखते हुए, पाटन रोधी ड्यूटी के वापस लेने की स्थिति में घरेलू उद्योग की विस्तार योजनाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा।
- viii मूल्य में कमी किए जाने के स्तर को देखते हुए स्पष्ट है कि पाटन रोधी ड्यूटियों को वापस लेने पर आयातित उत्पादन की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे घरेलू उद्योग के उत्पाद की मांग में कमी आएगी जिससे घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी होने की संभावना है।
- ix घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक क्षति के बजाय मूल्य क्षति का दावा किया है जो स्पष्ट रुप से लाभ; नकद प्रवाह और निवेश के प्रतिफल में कमी द्वारा स्थापित होता है। मूल्य में कमी के स्तर को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि पाटन रोधी ड्यूटियां खत्म होने पर आयातित उत्पाद की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होगी।
- x क्षमता बढ़ाना एक दीर्घकालिक निर्णय होता है और इस मामले में घरेलू उद्योग ने क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि प्रयोगकर्ताओं की मांग पूरी की जा सके।
- xi यदि निर्यातकर्ता, भारतीय बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए माल की आपूर्ति करना चाहते हैं तो सामान्य मूल्य पर न कि पाटित मूल्य पर माल का निर्यात का ऐसा किया जा सकता है। यदि मांग और पूर्ति में अंतर हो तो पाटनरोधी ड्यूटी अधिरोपित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- xii घरेलू उद्योग ने मालसूचियों के कारण क्षति का दावा नहीं किया है बल्कि लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह के रुप में क्षति का दावा किया है।
- xiii घरेलू उद्योग ने पारिश्रमिक रोजगार और उत्पादकता के कारण क्षति का दावा नहीं किया है। सरकारी कंपनी होने के कारण घरेलू उद्योग आवश्यक होने पर कर्मचारियों को न तो रख सकते हैं न निकाल सकते हैं।
- xiv घरेलू उद्योग को बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत नहीं बढ़ाने दिया गया जिससे भारी हानि हुई। विक्रय मूल्य में वृद्धि को लेकर कमी भी विवाद नहीं था।
- xv घरेलू उद्योग मैलामाइन के विनिर्माण के लिए अपनी ही यूरिया का इस्तेमाल करता है और यूरिया की कमी नहीं है। आधार वर्ष की तुलना में पारिश्रम लागत कम हुई है क्षति विश्लेषण में से असाधारण व्यय निकाल दिए गए है।
- xvi पाटन के कारण घरेलू उद्योग काफी प्रतिकूल रहा है। पाटनरोधी ड्यूटी के लागू होने के बावजूद विचाराधीन देश से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन आयातों के घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आ रही है तथा घरेलू मूल्य कम होते जा रहे हैं।
- xvii मैलामाइन के लिए चीन में नेमप्लेट उद्योग 1.8 मी.टन/प्रति वर्ष है जबिक खपत 1 मी.टन/प्रति वर्ष है। इसका अर्थ यह है कि औसत संयंत्र प्रचालन दर 50-60 प्रतिशत है। इसिलए पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त होने पर विचाराधीन देश के निर्यातकर्ता अपना उपयोग बढ़ाने के लिए बढ़ी मात्रा में भारत को निर्यात करेंगे। इसके अतिरिक्त चीन में अत्यधिक आपूर्ति के कारण सम्बद्ध देश के उत्पादकों को विदेशी बाजारों में अधिक निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे कम स्थानीय मांग से निपटा जा सके।

xviii आयातकर्ता, पाटन-रोधी शुल्क से बचने के लिए अत्यधिक मूलयांकन का सहारा ले रहे हैं और बेंचमार्क प्रकार की ड्यूटी निष्प्रभावी हो गई है। इसलिए, इसी कारण अधिक मात्रा और निर्धारित स्वरुप के साथ पाटन रोधी ड्यूटी का विस्तार किया गया है।

xix क्षिति का आंकलन करने के प्रयोजन से अमोनिया की लागत तय करने के लिए प्राकृतिक गैस के नान-एपीएम मूल्य पर विचार करने का अनुरोध किया क्योंकि अमोनिया, यूरिया के उत्पादन के लिए आवश्यक है और यह मैलामाइन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। अंतत: उर्वरक के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर कंपनी को उपलब्ध करवाई गई प्राकृतिक गैस इस प्रयोजन से पूरी तरह से असंगत है।

xx पूर्व अन्वेषण तथा वर्तमान अन्वेषण में संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल डी मिनिमस से ऊपर है बल्कि उल्लेखनीय भी है।

xxi यूरोपीय संघ ने विचाराधीन देश से वस्तु उत्पादों के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी ड्यूटी अधिरोपित की है। विचाराधीन देश के निर्यातकर्ता अनेक वर्षों से पाटन परिपाटी अपनाए हुए हैं और न केवल भारत में बल्कि तीसरे देश में भी पाटन करते रहे हैं। संबद्ध देश से विचाराधीन वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी ड्यूटी वापस ले ली जाने पर भी भारत में पाटन की संभावना बनी रहेगी।

xxii पाटनरोधी ड्यूटी अधिरोपित की जाने के बावजूद संबद्ध देश के मामले में आयात की मात्रा है उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जब पाटन रोधी ड्यूटी के होने पर भी संबद्ध देश से आयात में वृद्धि का रुख नजर आ रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी ड्यूटी वापस ले ली जाने पर भी मात्रा बढ़ेगी।

xxiii संबद्ध देश के उत्पादक विचाराधीन माल का उत्पादन करने के लिए भारी क्षमता बनाए रखते हैं।

xxiv पाटनरोधी ड्यूटी को वापस ले लिए जाने पर इस बात की संभावना है कि विचाराधीन देश से आयात किए जाने पर घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आएगी। कीमत में कमी आने से घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में और कमी करने के लिए बाध्य होंगे।

xxv चीनी उत्पादक पाटन मूल्य पर तीसरे देशों को बड़ी मात्रा में विचाराधीन माल का निर्यात कर रही है।

xxvi डी आर आई ने विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में अन्वेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि विचाराधीन उत्पाद के आयातकर्ता अधिमूल्यन कर आयात का उत्पाद कर रहे हैं तािक पाटनरोधी ड्यूटी से बच सकें। याचिकाकर्ता द्वारा यह आशंका जताई गई है कि पाटनरोधी ड्यूटी के लागू होने पर भी यदि ड्यूटी बचाने की ऐसी परिपाटी चल रही है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि पाटन रोधी ड्यूटी समाप्त कर दी जाने पर भी विचाराधीन देश का पाटित आयात उल्लेखनीय मात्रा में भारत में प्रवेश करेगा।

xxvii पाटनरोधी ड्यूटियों के होने के बावजूद चीनी आयात का बाजारी हिस्सा उल्लेखनीय है। सच्चाई यह है कि आयात का बाजारी हिस्सा वर्षों से बढ़ता रहा है और घरेलू उद्योग का हिस्सा घटता रहा है1

xxviii विचाराधीन देशों के सभी निर्यातकर्ता दुनिया भर में काफी ज्यादा निर्यात की और उन्मुख हैं।

xxix पाटन रोधी ड्यूटी के मौजूद न होने पर कीमतों में कमी सकारात्मक है।

xxx आयात कीमतें घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से काफी कम होती हैं। इसलिए उपभोक्ता पाटनरोधी ड्यूटी समाप्त की जाने पर आयातित उत्पाद खरीदने लगेगा जिससे उत्पाद के आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

xxxi घरेलू उद्योग पहले ही पाटित आयात कीमतों के कारण मूल्य का दबाव झेल रहा है क्योंकि पाटित आयात मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री के लागत से भी कम बैठते हैं। पाटनरोधी ड्यूटी को वापस ले लिए जाने पर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने विक्रय मूल्य में कमी करनी पड़ेगी जिससे इसे बिक्री की लागत के नीचे जाना पड़ेगा जिससे गंभीर मूल्य क्षति (प्राइस इंजरी) होगी1

xxxii पाटनरोधी ड्यूटी का संदर्भ स्वरुप पाटन रोकने में कारगर साबित नहीं हुआ है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 39. इस संबंध में इच्छुक पक्षकारों द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देश से आयात के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए सक्रिय होने से पूर्व घरेलू उद्योग को होने वाली वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने की दिशा में आगे बढ़ता है।
- 40. डब्लू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 तथा ऐडी नियमों के अनुबंध-2 में दोनों (क) समान प्रकार के उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करता है1 पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में भारत में अनन्य रुप में या उत्पादन या खपत के संदर्भ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पाटित आयातों की मूल्य प्रभावों के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना आवश्यक है कि भारत में समान उत्पाद के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में उल्लेखनीय कमी आई है या ऐसे आयातों के प्रभाव से मूल्य में काफी हद तक कमी आई है या मुल्य वृद्धि रुकी है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।
- 41. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियम के अनुबंध-2 के पैरा (iv) में इस प्रकार कहा गया है:
- 'संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का मूल्यांकन और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली बाते शामिल होंगी जैसे बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार शेयर, उत्पादकता, निवेश का प्रतिफल और क्षमता उपयोग में प्राकृतिक और संभावनायुक्त ह्रास; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव पर असर डालने वाले कारक"।
- 42. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित उद्योगों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर प्रभाव डालने वाले बातों पर ऊपर दिए गए नियम के अनुबंध (ii) के अनुसार विचार किया गया है।
- 43. कस्टम ट्रैफिक एक्ट की धारा 9(क)(5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी ड्यूटी ऐसे अधिरोपण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर प्रभावहीन हो जाएगी, जब तक पहली वापस न ली गई हो, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार, समीक्षा करने के बाद इस मत पर पहुंचती है कि ऐसी ड्यूटी समाप्त की जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है तो यह समय-समय पर ऐसे अधिरोपण की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा सकती है और ऐसी बढ़ी हुई अवधि इस प्रकार के विस्तार के आदेश की तारीख से आरंभ होगी।
- 44. वर्तमान जांच, लागू पाटनरोधी ड्यूटियों की हल्की समीक्षा है। नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित समीक्षा के मामले में भी लागू होंगे। इसलिए प्राधिकारी ने अनुबंध (ii) के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों में यथावश्यक परिवर्तन पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षिति निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी ड्यूटियां लागू हैं, प्राधिकारी विचार करता है कि घरेलू उद्योग को क्षिति होने की जांच करते समय चीन पी आर से विचाराधीन माल के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी ड्यूटियों पर विचार करना आवश्यक है या नहीं। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी उपाय पाटन का असर कम करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं जिससे क्षिति हो रही है।
- 45. चालू क्षित विश्लेषण के प्रयोजन से प्राधिकारी ने विचाराधीन माल के पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य प्रभाव का घरेलू उद्योग पर प्रभाव तथा मूल्य और लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जांच की है तािक क्षित की मौजूदगी और पाटन तथा क्षित के बीच सामान्य संबंध, यदि कोई हो, की जांच की जा सके। प्राधिकारी ने मेसर्स गुजरात राज्य अर्वरक और रसायन लिमिटेड, जो नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग है, से जुड़ी सूचनाओं पर विचार कर घरेलू उद्योग की क्षित की जांच की है। तदनुसार पाटित आयातों की मात्रा और मूलय के प्रभाव की जांच इस प्रकार की गई है:

पाटित उद्योगों की मात्रा का प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर असर

विवरण	यूनिटें	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई	निष्प्रभावित पीओआई
मांग						
चीन पीआर	एमटी	17,580	16,718	19,095	30,780	24,624
एमडीडी आकर्षित करने वाले देश	एमटी	11,976	12,222	15,443	16,339	13,071
अन्य देश	एमटी	731	1,797	5,861	6,741	5,393
घरेलू उद्योग	एमटी	13,319	15,284	14,022	18,537	14,830
अन्य भारतीय उत्पादक	एमटी	-	-	-	-	-
कुल मांग	एमटी	43,606	46,021	54,422	72,397	57,918
बाजार शेयर						
चीन पी आर	%	40.31	36.33	35.09	42.52	42.52
एडीडी आकर्षित करने वाले देश	%	27.46	26.56	28.38	22.57	22.57
अन्य देश	%	1.68	3.91	10.77	9.31	9.31
घरेलू उद्योग	%	30.54	33.21	25.77	25.61	25.61
अन्य भारतीय उत्पाद	%	-	-	-	-	-

मात्रा का प्रभाव

मांग और बाजारी हिस्सा

- 46. प्राधिकारी ने संबद्ध देश और अन्य देशों से आयात की मात्रा और मूल्य के आंकलन के लिए डी जी प्रणालियों द्वारा उपलब्ध करवाए गए लेन-देनवार आयात आकड़ों पर विचार किया है। संबद्ध उत्पाद के लिए मांग को सभी देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात तथा भारत के सभी घरेलू उत्पादकों की बिक्री के रुप में विचार किया गया है।
- 47. प्राधिकारी ने नोट किया है कि विचाराधीन माल की मांग में क्षित अविध से बाहर निरंतर वृद्धि हुई है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग का बाजारी हिस्सा वर्ष 2011-12 में बढ़ा है परंतु उसके बाद घटा है। चीनी पी आर के बाजारी हिस्से में लगातार वृद्धि हुई है।

आयात की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

- 48. पाटित आयात की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या अनन्य रुप से या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पाटन रोधी नियमों के अनुबंध-II (ii) में इस प्रकार प्रावधान किया गया है:
- ''पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या अनन्य रुप से या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 49. क्षति अवधि के लिए आयात की मात्रा इस प्रकार है।

विवरण	यूनिटें	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई	निष्प्रभावित
						पीओआई
आयात की मात्रा						
चीन पीआर	एमटी	17,580	16,718	19,095	30,780	24,624
एमडीडी आकर्षित करने वाले देश	एमटी	11,976	12,222	15,443	16,339	13,071
अन्य देश	एमटी	731	1,797	5,861	6,741	5,393
कुल	एमटी	30,287	30,737	40,399	53,860	43,088
संबद्ध देशों से आयात के संबंध में						
कुल आयात के संबंध में	%	58.04	54.39	47.27	57.15	57.15
भारतीय खपत के संबंध में	%	40.31	36.33	35.09	42.52	42.52
भारतीय उत्पादन के संबंध में	%	131.99	109.38	136.18	166.05	166.05

- 50. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते है कि:
- i चीन पी आर से पूरी क्षति अवधि के दौरान आयात में लगातार वृद्धि हुई है।
- ii कुल आयात में से चीन पी आर से किए गए विचाराधीन उत्पाद के आयात का हिस्सा पी ओ आई सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान काफी बड़ा है।
- iii कुल मिला कर सम्बद्ध देश से आयात भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में उल्लेखनीय बना रहा है।

मूल्य प्रभाव

पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर असर

51. सम्बद्ध देश से विचाराधीन वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले असर की जांच मूल्य कम होने, कम मूल्य पर बेचे जाने, मूल्य दबाव और मूल्य में कमी के संदर्भ में की गई है। इस विश्लषेण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) और क्षति रहित मूल्य की तुलना में सम्बद्ध देश के आयात के अवतिरत मूल्य से की गई है। अन्वेषण की अविध के दौरान विचाराधीन वस्तुओं की तुलना पाटित उद्योगों के अवतरण मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू विक्रय मूल्य से की गई। निवल उद्योग की निवल विक्रय वसूली (एन एस आर) निर्धारित करने के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कर, प्राप्त छूट और उद्ग्रहित कमीशन का समायोजन किया गया है। मूल्य से कम पर बिक्री क्षति के आकलन का महत्वपूर्ण संकेतक है; इस प्रकार प्राधिकारी ने एक क्षति रहित मूल्य तैयार कर उसकी तुलना अवतरित मूल्य से की है तािक कम मूल्य पर बिक्री की सीमा की जानकारी प्राप्त की जा सके। पाटनरोधी नियमों के अनुबंध के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहत मूल्य का मूल्यांकन किय गया है। स्थित इस प्रकार है:-

कम मूल्य और बिक्री से कम मूल्य

52. प्राधिकारी ने अग्रवर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित कारणों से शुल्क मुक्त आयातों के तहत आदानों के अवतरित मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद पाटन विरोधी ड्यूटी सहित और पाटन विरोधी ड्यूटी रहित कम मूल्य और बिक्री से कम मूल्य को विश्लेषण किया है:-

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
निवल बिक्री मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***
अवतरित मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***
मूल्य में कमी	रु./एमटी	***	***	***	***
मूल्य में कमी	%	***	***	***	***
मूल्य में कमी	%रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10

53. उपरोक्त आंकड़े लागू पाटन रोधी ड्यूटी को ध्यान में रखे बिना मूल्य में कमी का संकेत देते हैं जो महत्वपूर्ण है।

बिक्री से कम मूल्य

54. मूल्य से कम पर बिक्री क्षित के आंकलन का महत्वपूर्ण संकेतक है। इस प्रकार प्राधिकारी ने एक क्षित रहित मूल्य तैयार कर उसकी तुलना अवतरित मूल्य से की है ताकि कम मूल्य पर बिक्री की सीमा की जानकारी प्राप्त की जा सके। पाटित आयातों की मूल्य से कम पर बेचने की जांच करने के लिए उपरोक्त पैरा 52 के अनुसार आयातों के अवतरित मूल्य की तुलना निर्धारित किए गए क्षित रहित मूल्य से की गई है जिसमें लागू पाटनरोधी ड्यूटी को ध्यान में रखा गया है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
क्षति रहित मूल्य	अमेरिकी डालर/एमटी	***
अवतरित मूल्य	अमेरिकी डालर/एमटी	***
मूल्य से कम पर बिक्री	अमेरिकी डालर/एमटी	***
मूल्य से कम पर बिक्री	%	***
मूल्य से कम पर बिक्री	%रेंज	20-30%

उपरोक्त तालिका से प्राधिकारी नोट करते है कि पी ओ आई के दौरान मूल्य से कम पर बिक्री चीन के लिए सकारात्मक थी।

पाटित आयातों के मूल्य दबाव और मंदी का प्रभाव

55. इस बात की जांच करने के लिए कि क्या सम्बद्ध देश के पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू मूल्यों पर दबाव पड़ता है या उनमें मंदी आती है, घरेलू उद्योग के भारित औसत बिक्री वसूली के रुख की तुलना बिक्री की लागत और अवतरित मूल्यों से की गई है जैसा कि ऊपर पैरा 52 में उल्लेख किया गया है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
अवतरित मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	101	105	113
बिक्री की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	105	134	167
विक्रय मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	95	103	113

56. उपरोक्त जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अविध के दौरान बिक्री की लागत और विक्रय मूल्य दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तथापि क्षति अविध के दौरान विक्रय मूल्य में वृद्धि, विक्रय की लागत में वृद्धि के अनुपात में नहीं थी। यह मूल्य दबाव का प्रभाव दर्शाता है जिसके कारण घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुरुप विक्रय रुप में वृद्धि नहीं कर सका है।

घरेलू उद्योगों से संबंधित आर्थिक पैरामीटरों की जांच

57. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 2 में कहा गया है कि क्षित के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले इन आयातों के परिणामी प्रभाव का वस्तुनिष्ठ परीक्षण शामिल होगा। इन नियमों में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का वस्तुनिष्ठ और पूर्वाग्रहरहित आंकलन तथा उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली बातें शामिल होंगी। नियमों में यह भी प्रावधान है कि संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का मूल्यांकन और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली बाते शामिल होंगी जैसे बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार शेयर, उत्पादकता, निवेश का प्रतिफल और क्षमता उपयोग में प्राकृतिक और संभावनायुक्त हास; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षित पैरा मीटरों पर नीचे चर्चा की गई है।

क्षमता उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

58. उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिटें	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई	निष्प्रभावित पीओआई
क्षमता	एमटी	15,000	15,000	15,000	18,750	15,000
उत्पादन	एमटी	13,938	15,280	13,998	18,102	14,482
क्षमता उपयोग	%	92.92%	101.87%	93.32%	96.54%	96.54%
घरेलू बिक्री	एमटी	13,319	15,284	14,166	18,558	14,847

59. ऊपर दी गई जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूरी क्षति अवधि के दौरान पूर्वत बनी रही है। तथापि याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि देश में मैलामाइन की मांग और पूर्ति में अंतर को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता अपनी क्षमता को बढ़ाकर 40,000 एमटी करने की प्रक्रिया में है। आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष दोनों की तुलना में पी ओ आई में घरेलू उद्योग का उत्पादन बिक्री और क्षमता उपयोग बढ़ा है।

60. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जी एस एफ सी भारत में मांग को पूरा करने में असमर्थ है और मांग और पूर्ति में भारी अंतर है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी ड्यूटी का प्रयोजन अनुचित व्यापार प्रणालियों को दूर करना है न कि भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के आयातों को प्रतिबंधित करना है। आगे यह भी नोट किया जाता है कि पाटन रोधी ड्यूटियों का प्रयोजन आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रणालियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान से बचाना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके जो भारत के आम हित में हो। पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण सम्बद्ध देशों से आयात को किसी प्रकार प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ताओं की उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी इस संबंध में विगत की अपनी सतत स्थिति का संदर्भ देता है और डी एस एम इडेमिट्स लिमिटेड बनाम नामोदिष्ट प्राधिकारी मुकदमे में 'सीसेट' के निर्णय पर भरोसा करता है। यदि निर्यातकर्ता भारतीय बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामानों की आपूर्ति करना चाहते हैं तो पाटन रहित मूल्य पर निर्यात कर ऐसा किया जा सकता है।

मालसूची

61. ऊपर दी गई जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्वेषण की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति में गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	183	160	75

लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह

62. क्षति-अवधि के दौरान लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

विवरण	यूनिटें	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई	निष्प्रभावित पीओआई
बिक्री लागत	रु/एमटी	***	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	105	134	167	167
विक्रय मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	95	103	113	113
लाभ (हानि)	रु/एमटी	***	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	71	28	-18	-18
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***	***

ट्रेंड	संकेतित	100	82	29	-20	-20
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	82	31	-19	-19
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	83	38	-6	-6
आर ओ सी ई	%	***	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	67	28	-17	-17

63. उपर्युक्त जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लाभ/हानि तथा घरेलू उद्योग की लाभप्रदाता में पूरी क्षति अवधि के दौरान ह्रास हुआ है। जबिक पूरी अवधि के दौरान उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है, उत्पादन लागत में वृद्धि विक्रय मूल्य में वृद्धि से अधिक थी। इसके परिणामस्वरुप क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई। अन्वेषण की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वित्तीय हानि होनी शुरु हुई। इसी प्रकार नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में भी गिरावट देखने को मिली।

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

64. नीचे दी गई जानकारी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में अन्वेषण अविध के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार की स्थिति में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में अन्वेषण अविध के दौरान भुगतान की गई मजदूरी में गिरावट आई है परंतु पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। इस अविध के दौरान दैनिक उत्पादन की दृष्टि से और प्रति कर्मचारी समान उत्पादकता रेंज में बनी रहे।

विवरण	यूनिटें	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई	निष्प्रभावित पीओआई
रोजगार	सं.	***	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	98	98	104	104
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	118	50	86	86
दैनि उत्पादकता	एमटी/प्रतिदिन	***	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	110	100	104	104
प्रतिकर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***	***
ट्रेंड	संकेतित	100	112	102	100	100

पाटन की मात्रा

65. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन पी आर से विचाराधीन माल का पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण है।

वृद्धि

66. प्राधिकारी नोट करते है कि बिक्री उत्पादन और क्षमता उपयोग की दृष्टि से घरेलू उद्योग में वृद्धि सकारात्मक थी जबिक लाभ, निवेश पर प्रतिफल तथा नकद लाभ के संबंध में वृद्धि नकारात्मक थी:

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
उत्पादन में	%	-	9.63	(8.39)	3.46
घरेलू बिक्री में	%	-	14.75	(7.31)	4.80
क्षमता उपयोग में	%	-	9.63	(8.39)	3.46
बिक्री की लागत में	%	-	***	***	***
विक्रय मूल्य में	%		***	***	***
	70	-			
लाभ/हानि में	%	-	***	***	***

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

67. घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि इसने 7,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की योजना बनाई है जो अनेक उत्पादों के लिए है। इसमें मैलामाइन के लिए उल्लेखनीय क्षमता विस्तार शामिल है। कंपनी का तर्क है कि इसका उद्देश्य मैलामाइन की क्षमता बढ़ाकर 40,000 एमटी करना है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि मैलामाइन के लगातार पाटन से उत्पाद के संबंध में कंपनी की विस्तार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद का सतत पाटन तथा उत्पादन में वित्तीय हानि से पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि घरेलू उद्योग एक बहु उद्योग कंपनी है, इस उत्पाद के कारण घरेलू उद्योग के प्रचालन निष्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से विचाराधीन माल के लिए पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।

सामान्य लिंक

68. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की क्या अन्य ज्ञात कारकों ने निम्नानुसार घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाया होता।

तृतीय देशों से आयात की मात्रा और मूल

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी ओ आई के दौरान सम्बद्ध देश से इतर देशों से सम्बद्ध माल के आयात पर या तो पाटन रोधी ड्यूटी लगाई जा रही है या वे महत्वपूर्ण नहीं हैं।

मांग का संकुचन तथा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में संकुचन नहीं है। क्षति अवधि के दौरान उत्पाद के लिए मांग बढ़ी है।

प्रौद्योगिकी में विकास

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी इच्छुक पक्षकार ने इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चलता है कि प्रौद्योगिकी में ऐसा परिवर्तन हुआ हो जिससे डी आई को क्षति हुई है।

प्रतिस्पर्धा की स्थितियां तथा व्यापार को प्रतिबंधित करने वाली परिपाटियां

72. प्राधिकारी नोट करते है कि विचाराधानी वस्तुओं के आयात में कोई कठिनाई नहीं है। घरेलू उद्योग विचाराधानी वस्तुओं का एममात्र उत्पादक है।

घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

73. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन संगत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने क्षति का आंकलन करने के लिए प्राधिकारी द्वारा घरेलू और निर्यात बाजार में मूल्य और लाभप्रदता को अलग-अलग कर दिया गया है।

अन्य उत्पादों का निष्पादन

- 74. घरेलू उद्योग के लिए दावा की गई क्षति विचाराधीन उत्पाद के कारण होती है। याचिकाकर्ता ने ऐसी सूचनाएं उपलब्ध करवाई हैं जो केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित होती है। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दी गई वित्तीय सूचनाओं से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची गई समान वस्तुओं के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति स्पष्ट होती है।
- 75. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि हालांकि उपरोक्त सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारणों से निर्धारित क्षति हुई नहीं प्रतीत होती, निम्नलिखित पैरामीटरों से स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटन रोधी ड्यूटी समाप्त कर दी जाने पर पाटित आयात के कारण होती है।
- संबंद्ध देश से विचाराधीन माल के आयात की मात्रा काफी महत्वपूर्ण है।
- संबद्ध देशों से विचाराधीन माल के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं।
- iii उपभोक्ताओं द्वारा आयातित उत्पादों को अपनाने में घरेलू उद्योग के उत्पादों की मांग में कमी आएगी और पाटित उत्पाद की मांग बढ़ेगी।
- iv सम्बद्ध देशों से विचाराधीन माल के आयात पर पाटनरोधी ड्यूटियां लागू होने के बावजूद, इस स्नोत से उल्लेखनीय मात्रा में पाटित निर्यात होता रहता है। इससे संकेत मिलता है कि यदि इसे समाप्त भी कर दिया जाए, पाटन और बढ़ेगा तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाएगा।
- v पाटनरोधी ड्यूटी समाप्त कर देने पर संबद्ध देश के निर्यातकर्ता अपनी अधिक उत्पादन क्षमताओं तथा कम निर्यात मूल्यों के कारण बाजार पर पुन: कब्जा जमा लेगा।

क्षति और कारण के संबंध में निष्कर्ष

76. इस प्रकार अन्वेषण से पता चला है कि पूरी क्षित अविध के दौरान चीन पीआर से पाटित आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। जहां तक मूल्यों पर पाटित आयात के प्रभाव का संबंध है, चीन पी आर से पाटित आयात के प्रभाव से मूल्यों में और बिक्री मूल्य में काफी कमी आई है जबिक भारत के समान प्रकार के उत्पाद में इतनी कमी नहीं आई थी और ऐसे आयातों का असर यह हुआ कि ऐसे आयातों को काफी हद तक मूल्यों को दबाना पड़ा। घरेलू उद्योग पर चीन पी आर से होने वाले पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में अन्वेषण से पता चला है कि बाजारी हिस्सेदारी, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल जैसे प्राचलों के रुप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी ह्रास हुआ है। अन्वेषण से ज्ञात हुआ है कि चीन पी आर से विचाराधीन वस्तुओं के पाटित आयात से क्षित हुई है।

क्षति तथा क्षति मार्जिन की मात्रा

77. प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन माल का गैर हानिकारक मूल्य की तुलना संबद्ध देश से किए गए आयात के अवतरित मूल्य से की गई है ताकि पी ओ आई के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वित्तीय रिकार्डों का सत्यापन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैलामाइन के विनिर्माण के लिए एपीएम गैस का विचालन प्रयोग नहीं किया गया है तथा मैलामाइन के विनिर्माण के लिए केवल गैर एपीएम का प्रयोग किया गया है। पीओआई के दौरान संबंद्ध देश के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन इस प्रकार है।

विवरण	यूनिट	चीन पीआर /पीओआर
गैर हानिकारक मूल्य	अमेरिकी डालर/ एमटी	***
अवतरण मूल्य	अमेरिकी डालर/ एमटी	***
क्षति मार्जिन	अमेरिकी डालर/ एमटी	***
क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन	% रेंज	20-30

उपरोक्त सारणी से प्राधिकारी नोट करते है कि पीओआई के दौरान क्षति सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

- 78. वर्तमान अन्वेषण, चीन पी आर से आयातित विचाराधीन वस्तुओं पर अधिरोपित पाटन रोधी ड्यूटियों की सामान्य समीक्षा है। नियमों के अधीन प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि क्या लगातार पाटन रोधी ड्यूटी बनाए रखना आवश्यक है। इसमें इस बात की जांच की जानी भी आवश्यक होती है कि क्या अधिरोपित ड्यूटी से क्षित पहुंचाने वाला पाटन/समाप्त करने का उद्देश्य पूरा हो रहा है।
- 79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान अन्वेषण में चीन पीआर से विचाराधीन माल के लगातार पाटन में घरेलू उद्योग को लगातार हानि हो रही है जिससे संबद्ध देश से पाटन और क्षित की संभावना का पता चलता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए और विचाराधीन माल की मांग और कीमत के संबंध में अनुकूल बाजारी स्थितियों के कारण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पाटनरोधी ड्यूटियों को वापस लेने/समाप्त करने पर चीन पीआर से पाटन बढ़ सकता है। निम्नलिखित विश्लेषण से स्पष्ट होगा कि पाटनरोधी ड्यूटियों को वापस लेने की स्थिति में पाटन के जारी रहने/बढ़ने तथा घरेलू उद्योग को क्षिति की संभावना बनी रहेगी।

(i) चालू और विगत पाटन मार्जिन का स्तर

80. पूर्ववर्ती तथा वर्तमान अन्वेषणों में चीन के संबंध में पाटन मार्जिन का स्तर महत्वपूर्ण है। चीन पी आर से विचाराधीन माल के आयातों से मूल्य कम होने तथा मूल्य से कम पर बेचे जाने संबंधी होने वाले प्रभाव के स्तर को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी ड्यूटी वापस ली जाने पर पाटित आयात की मात्रा और बढ़ेगी। मूल अन्वेषण के निष्कर्षों के पाटन मार्जिन *** प्रतिशत *** प्रतिशत के बीच निर्धारित किए गए थे और सामान्य (सनसेट) समीक्षा अन्वेषण में निर्धारित पाटन मार्जिन लगभग *** प्रतिशत था।

(ii) पाटन रोधी ड्यूटी यूरोपीय संघ

81. यूरोपीय संघ ने संबंद्ध देश में विचाराधीन माल के आयात के लिए पाटनरोधी ड्यूटी अधिरोपित कर रखी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी पाटित मूल्य पर तीसरे देशों को उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और पाटनरोधी ड्यूटी वापस ली जाने की स्थिति पाटित आयात की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।

(iii) उपायों के न होने के कारण मूल्य कम होना दबाव, मंदी

82. जिन मूल्यों पर चीनी पीआर से विचाराधीन वस्तुएं आयातित की जा रही हैं वे उस मूल्य से काफी कम है जिन पर घरेलू बाजार में माल बेचे जा रहे हैं। इसलिए, पाटनरोधी ड्यूटियों के वापस लिए जाने/समाप्त किए जाने की स्थिति में इस बात की संभावना है कि निर्यातकर्ता अपनी महत्वपूर्ण क्षमता के अनुसार भारतीय बाजार में अपने उत्पादन भेजने के लिए चैनल तैयार कर सकते है।

(iv) सम्बद्ध देश में भारी उत्पादन क्षमता

83. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करवाए गए साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि चीन में मैलामाइन के लिए नेमप्लेट क्षमता लगभग 1.8 मी.टन/प्रति वर्ष है जबिक प्रति वर्ष खपत लगभग 01 मी.टन है। इससे स्पष्ट होता है कि औसत संयंत्र प्रचालन दर 50-60 प्रतिशत है और इस प्रकार चीन पी आर में अतिरिक्त क्षमता होने का पता चलता है।

(v) तृतीय देशों के निर्यात के संबंध में पाटन मार्जिन

84. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से ज्ञात होता है कि चीन के उत्पादक/निर्यातकर्ता तृतीय देशों को पाटित मूल्य पर बड़ी मात्रा में विचाराधीन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं।

पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निष्कर्ष

85. पाटनरोधी ड्यूटियों अधिरोपित की जाने के बावजूद सम्बद्ध देशों से आयात के वर्तमान स्तर पर विचार करते हुए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटन रोधी ड्यूटी समाप्त की जाने की स्थिति में पाटन के बढ़ने और परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को क्षिति पहुंचने की पूरी संभावना है। यह भी नोट किया गया है कि आयात मूल्य के कारण घरेलू मूल्य में कमी आई है तथा इसका घरेलू मूल्यों पर उल्लेखनीय दबावकारी प्रमाण पड़ा है।

इच्छुक पक्षकारों का पश्च प्रकटन निवेदन

86. प्राधिकारी यह नोट करते है कि प्रकटन विवरण घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षकारों को भेजा गया था। मेसर्स टीपीएम (घरेलू उद्योग की ओर से) मेसर्स लक्ष्मी कुमारन और श्रीधरन (एक्सीम कार्य की ओर से), मेसर्स ई ऐंड वाई (मेसर्स सेंचरी प्लाई बोर्ड (इंडिया) लिमिटेड के प्रतिनिधि, मेसर्स ब्लूम डेकोर लिमिटेड, मेसर्स मेघदूत लैमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड लैमिनेट मैन्युफैक्चर्स एसोसिऐशन) और मेसर्स संदीप आर्गेनिक्स द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं।

घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

- 87. मेसर्स बालाजी एक्शन बिल्डवेल ने काफी दर से 30 अक्तूबर, 2015 को अपना निवेदन दाखिल किया था। साथ ही 11वें माह में इच्छुक पक्षकार ने केवल अपना विरोध दर्ज करवाया है और ऐसी कोई सूचना दाखिल नहीं की है जो उन्हें आयातकर्ता की प्रश्नावली के उत्तर में दाखिल करनी होती है। मेसर्स बालाजी एक्शन बिल्डेवल की द्वारा जमा किया गया पूरा निवेदन 9 जनवरी, 2012 के ट्रेड नोटिस सं.01/2012, शुरुआती अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय सीमा, नामोद्दिष्ट प्राधिकारी और डब्लयू टी ओ पैनल तथा अपीलीय संस्था रिपोर्ट की विगत परिपाटी को देखते हुए अस्वीकार किया जा सकता है।
- 88. जिस प्रयोजन से पाटन रोधी ड्यूटियों अधिरोपित की जाती हैं उस प्रयोजनार्थ पाटनरोधी ड्यूटी (ड्यूटी का निश्चित प्रकार) की निश्चित मात्रा के रुप में अधिरोपित की जा सकती है। कच्चे माल की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे लागत में वृद्धि हुई फलत: निर्यात मूल्य में वृद्धि हुई। तथापि, संदर्भ मूल्य पूर्ववत बना रहा और इसलिए पाटन रोधी ड्यूटी पूरी तरह से बेअसर हो गई है। कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने के कारण संदर्भ मूलय की तुलना में एनआईजी काफी अधिक होता है।

प्रकटन कथन के संबंध में आयातकर्ताओं, उपरोक्ताओं तथा अन्य इच्छक पक्षकारों की टिप्पणियां

- 89. प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध किया जाता है कि क्या याचिकाकर्ता जो समीक्षाधीन संबद्ध देश या अन्य देशों से आयात करता है, पाटन रोधी ड्यूटी के तहत सुरक्षा प्राप्त करने का पात्र है विशेष रुप से इंडियन ए डी रुल्स के रुल 2(क) तथा डब्ल्यू टी ओ ए डी करार के अनुच्छेद 4.1 की रोशनी में जिसमें यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि समीक्षाधीन माल के आयातकर्ता घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर किए जा सकते हैं।
- 90. घरेलू उद्योग का यह दावा कि एडवांस लाइसेंस मैकेनिकल के तहत किए गए आयात घरेलू उद्योग की कीमत और बाजार को अभिशासित कर रहे हैं, पूरी तरह से अस्वीकार करने योग्य है।
- 91. सामान्य मूल्य निर्धारित करने से पूर्व प्राधिकारी के लिए यह भी आवश्यक है कि वे चीनी विनिर्माताओं तथा भारत के घरेलू उत्पादकों के व्यापार के स्तर की जांच करें। भारत के घरेलू उत्पादकों की उत्पादन और बिक्री के संबंध में सीमाएं है क्योंकि इन्होंने उत्पादन करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दे रखा है। इसके विपरीत, चीनी उत्पादक अपनी प्रौद्योगिकी और ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तथा उत्पादन बिक्री और निर्यात के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

- 92. डीजीसीआईएस द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े उस मूल्य के प्रतिनिधि है जिस मूल्य पर विचाराधीन माल भारत में प्रवेश कर रहे हैं और बिलकुल हाल में विचाराधीन माल के निर्यात के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक रिपोर्ट से इसकी और पृष्टि हो जाती है जिससे स्पष्ट होता है कि डीजीसीआईएस आंकड़ों की तुलना में काफी अधिक आयात मूल्य है।
- 93. दो तिहाई आयात लेन-देन को समाप्त करने के संबंध में डीआरआई द्वारा जारी किये गये सचेतक परिपत्र पर निर्भरता त्रुटिपूर्ण है क्योंकि डी आर आई द्वारा सचेतक परिपत्र जारी करना क्षेत्रीय फार्मेशनों के लिए केवल सावधान करना मात्र है। डीआरआई ने कारण बताओ जारी नहीं किया है। साथ ही, जीएसएफसी द्वारा प्रस्तुत किया गया डीआरआई एलर्ट न उनके और न उनके प्रतिनिधि के पत्र शीर्ष पर था।
- 94. पाटन तथा क्षति विश्लेषण के लिए गैर ड्यूटी मुक्त आयात मूल्य का प्रयोग करना प्राधिकारी की सतत परिपाटी रही है और विचाराधीन अन्वेषण में इस परिपाटी में परिवर्तन करने का. कोई औचित्य नहीं है।
- 95. यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू उत्पादक ने विशिष्ट रूप से कब कहा कि इसने किसी मात्रात्मक क्षित के लिए दावा नहीं किया है क्योंकि ऐसी कोई क्षित हुई ही नहीं है, तब नामोद्दिष्ट प्राधिकारी ने वैसी मात्रात्मक क्षित की जांच ही क्यों की और यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में ऐसी क्षित हुई है।
- 96. जहां तक विचाराधीन माल का संबंध है, भारत में मांग और पूर्ति में भारी अंतर है। इसलिए यह कथन कि पाटन रोधी अधिरोपण के बावजूद चीन से आयात किए जाने वाले माल की मात्रा, उल्लेखनीय है, इसलिए ड्यूटी हटाई जानी चाहिए भ्रामक है।
- 97. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों के अनुसार केवल ड्यूटी मुक्त आयातों के लिए आयात मूल्य अंगीकार करना उचित नहीं है। निर्यात आंकड़ों के साथ-साथ सभी आंकड़ों (सशुल्क और शुल्क मुक्त) पर विचार किया जाना चाहिए।
- 98. सिंटन ग्रेड के मैलामाइन का आयात किया जाता है और तुलना करने के लिए भारित औसत बिक्री की वसूली उचित नहीं है।
- 99. घरेलू उत्पादक, ऐसे स्रोत से कच्चा माल खरीद रहा है जो ज्यादा मूल्य प्रभारित कर रहा है। उर्वरक के विनिर्माण के लिए जरूरी मुख्य कच्चा माल घरेलू उत्पादक को बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध है। इसलिए, कच्चे माल का अत्यधिक बढ़ा हुआ मूल्य अवैध है।
- 100. प्रतिवादी ने प्राधिकारी के इस निष्कर्ष पर सवाल उठाया है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन काफी बदतर होता है जब अंग्रकित स्थितियों में घरेलू उत्पाद के बाजारी हिस्से में वृद्धि होती है (i) जब विचाराधीन माल की मांग बढ़ती है (ii) घरेलू उत्पादक 100 प्रतिशत उत्पादन क्षमता के आसपास प्रचालन कर रहा है तथा पूरा माल बेचने में सक्षम है; और (iii) खपत तथा आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादक द्वारा आयात किया जाता है।
- 101. प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह इस बात को ध्यान में रखें कि मेसर्स जीएसएफसी में बंदी हुई थी और वर्तमान में यह अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है, कतर से विचाराधीन वस्तुओं का आयात कर रहा है और एकाधिकारी स्थिति का लाभ उठा रहा है।
- 102. घरेलू उद्योग को पाटन से इतर कारणों से क्षति हुई है, किसी उचित तुलना के लिए इसकी मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए और इसे अलग किया जाना चाहिए, जैसा कि यूएस हाट रोल्ड स्टील मामले में डब्लयू टी ओ डी एस बी अपीलीय निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 103. निर्दिष्ट प्राधिकारी अमेरिकी डालर में ड्यूटी (शुल्क) की सिफारिश करता है हालांकि भारत की मुद्रा रुपया है। एडीए में अन्य देशों की मुद्रा के रुप में पाटन रोधी ड्यूटी अधिरोपित करने का प्रावधान नहीं है।

- 104. एनआईपी को अमेरिकी डालर में परिवर्तित करते समय भी प्राधिकारी ने अत्यधिक अवमूल्ति भारतीय रुपये को ध्यान में रखते हुए अचानक प्राप्त लाभों का घरेलू उद्योग में जोड़ा। प्राधिकारी को वर्तमान परिवर्तन मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए था न कि उस परिवर्तन मूल्य को जो पीओआई के दौरान प्रचालित था।
- 105. प्राधिकारी, संदर्भ मूल्य को कच्चे माल के सूचकांक से संबद्ध करने के लिए कोई तरीका निर्धारित कर सकते हैं ताकि ड्यूटी का संकलन प्रचलित क्षति पाटन मार्जिन से अधिक न हो सके।
- 106. घरेलू उद्योग के लिए यह दावा करना गलत होगा। डयूटी का तरीका उसी रीति से होना चाहिए जैसा कहा गया है। ड्यूटी का स्वरुप माननीय प्राधिकारी द्वारा चुना जाता है जिसमें इस विषय पर सभी हितबद्ध पक्षकारों के हितों का संज्ञान लिया जाता है तथा प्रत्येक मामले में गुण दोष को ध्यान में रखा जाता है।
- 107. प्राकृतिक गैस और यूरिया के मूल्य में विश्व भर में कमी होने के बावजूद फर्जी आंकड़ों के आधार पर पाटन रोधी ड्यूटी अभी भी जारी है।
- 108. आयात का अवतरित मूल्य अधिक होता है और आयातकर्ता नुकसान उठा रहे हैं; और एडीडी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि 10 वर्षों से अधिक समय से इस उत्पाद में पहले से ही एडीडी शामिल है।
- 109. 5 वर्षों से एन आई पी का नियतन मनमानीपूर्ण और तर्कहीन है। अंतिम उत्पाद तैयार करने के लिए बाजार में भेजे जाने वाले एकमात्र आदान की संकेतित लागत की तर्ज पर इसकी प्रत्येक तीन माह पर समीक्षा कर इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। आई ओ की मिली-भगत से गलत ढंग से तैयार किए गए आंकड़ों के आधार पर मनमानी तरीके से तैयार किया गया अनुचित एनआईपी नियमन प्राधिकारी के लिए शोभनीय नहीं है।
- 110. यदि याचिकाकर्ता के विचाराधीन माल का आयात सामान्य था तथा सुविधा बंद होने के कारण अंतर पूरा करने के लिए था तो बंदी के दौरान ए डी ड्यूटी का प्रचालन करने की अनुमित कयों दी गई क्योंकि बंदी की अविध के दौरान उन्हें कोई क्षिति नहीं हो रही थी।
- 111. कानून में, सार्वजनिक या मौखिक सुनवाई की अवधारणा नहीं है बल्कि सुनवाई की जाने की बाध्यता है तथा इसका अर्थ है बनाए गए मुद्दों के विरुद्ध व्यक्तिगत सुनवाई। हमें यह जानना चाहिए कि प्राधिकारी द्वारा प्राप्त तथ्य कोई प्रतिवाद किए जाने से पूर्व के हैं।
- 112. डी आई के अंत-स्टाक के मूल्य में दर्शाई गई निर्माण लागत एक सार्वजनिक दस्तावेज है; और प्राधिकारी कृत्रिम अवतरित मूल्य को गोपनीय रखने का कारण बता सकते हैं।
- 113. कार्यवाही प्रशासनिक दृष्टि से चलाई जाती न कि अर्द्ध-न्यायिक दृष्टि से और प्राथमिक रुप से प्राप्त तथ्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स जीएसएफसी नामक घरेलू उत्पादक ने विचाराधीन माल का आयात संबद्ध देशों से न कर असम्बद्ध देशों से किया है जो उत्पादन की तुलना में 13.48 प्रतिशत है, कुल आयात का 4.33 प्रतिशत है तथा पीओआई में भारतीय खपत के संबंध में 3.37 प्रतिशत है।
- 115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इ यू, ईरान, इंडोनेशिया और जापान से उसी उत्पाद के 01 जून, 2012 के अंतिम निष्कर्ष में डी आई द्वारा उसी स्तर का आयात किया गया। उस अंतिम निर्धारण में प्राधिकारी ने यह भी कहा था कि यद्यपि मेसर्स जीएसएफसी ने विचाराधीन माल का आयात कर बेचा था, मेसर्स जीएसएफसी का बल आयात की ओर नहीं गया है तथा कंपनी एक महत्वपूर्ण व्यापारी के रुप में कार्य नहीं कर रही है। कंपनी द्वारा उत्पादक के रुप में अपना उत्पादन करने पर बल दिया जाना जारी है। प्राधिकारी का मत है कि मेसर्स जी एस एफ सी का व्यवहार अभी भी उत्पादक का है और और भी इसकी योजना अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 40,000 एमटी करने की है।

- 116. वर्तमान अन्वेषण में पीओआई में संबद्ध देश से विचाराधीन माल को आयात न करने के संबंध में प्राधिकारी का मत है कि नियम 2(ख) के अर्थ के अनुसार मेसर्स जीएसएफसी घरेलु उद्योग है।
- 117. प्राधिकारी का मत है कि श्रेणी और गुणवत्ता के संबंध में उठाए गए मुद्दों के संबंध में संबद्ध पक्षकारों द्वारा आंकड़ों या साक्ष्य के जरिए मात्रा या उदाहरण नहीं दिया गया है। चीन पी आर से किसी उत्पादक/निर्यातकर्ता ने सहयोग करते हुए इन मुद्दों के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित नहीं किया गया है और संबद्ध देश से आयातित माल तथा घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित माल ''समान वस्तु'' माने जाते हैं।
- 118. जहां तक एडवांस लाइसेंस रुट के तहत संदर्भ दिए जाने के बारे में विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा दिए गए मत का संबंध है, प्राधिकारी का मत है कि अधिकांश नान-एडंवास लाइसेंस रुट आयात मूलय, डीआरआई अन्वेषण की रोशनी में उचित और यथार्थपरक नहीं प्रतीत होते। प्राधिकारी ने नोट किया है कि चीन सीमा शुल्क आंकड़ों के तहत भारत को उपलब्ध निर्यात मूल्य केवल एडवांस लाइसेंस रुट के तहत न कि नान एडवांस लाइसेंस रुट के तहत भारत से संबंध रखता है। प्राधिकारी ने विगत में लगातार यह विचार व्यक्त किया है कि एडवांस लाइसेंस के तहत भी मूल्य क्षति करते हैं क्योंकि ये आयात भी घरेलू उद्योग को निर्यातकर्ताओं का अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग को उपलब्ध अवसर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और उस सीमा तक विचाराधीन माल की मांग भी घट जाती है। यह भी नोट किया जाता है कि यह प्राधिकारी की सतत प्रणाली है कि घरेलू उद्योग की हुई क्षति का आंकलन करने के उद्देश्य से आयात को ड्यूटी छूट में शामिल किया जाता है।
- 119. जहां तक सामान्य मूल्य का संबंध है, विभिन्न इच्छुक पक्षकारों, जो मुख्य रुप से आयातकर्ता हैं, द्वारा उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा चीनी माल के लागत लाभ के संबंध में निवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातकर्ता ने सहयोग नहीं किया है। विनिर्माण प्रक्रिया और उत्पादन ब्यौरे के संबंध में किसी प्रकार की प्रतिक्रया न प्राप्त होने पर प्राधिकारी के पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना का संदर्भ देने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।
- 120. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने नियम के अनुबंध-। के पैरा 7 के द्वितीय परंतुक की शर्तों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जैसी कि इसकी हमेशा अपनाई जाने वाली प्रणाली है जिसमें कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग मानकों और उपयोगिताओं के इष्टम लागत, परिवर्तन लागत, एस जी ए व्यय और घरेलू उद्योग के व्यय के संदर्भ में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है।
- 121. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजीसीआई ऐंड एस, डीजी सिस्टम तथा चीन कस्टम के तहत यथाउपलब्ध अन्वेषण अविध में विचाराधीन माल के आयात की मात्रा कुल मिलाकर परस्पर संबंधित है। इस प्रकार, विभिन्न मात्रात्मक निष्पादन के लिए संबद्ध देश से विचाराधीन माल की मात्रा के संदर्भन पर आधारित मात्रा प्रभाव का क्षित मूल्यांकन तीनों स्रोत के तहत उपलब्ध आंकड़ों में से किसी को अपनाने पर भिन्न-भिन्न नहीं होते।
- 122. मूल्य प्रभाव के लिए आयातकर्ताओं द्वारा अपनाए गए इनवाइसिंग पहलू तथा डी आर आई द्वारा अन्वेषण और रिपोर्ट किए गए को देखते हुए प्राधिकारी ने एडवांस लाइसेंस रुट के मूल्य को स्वीकार किया है जो मोटे तौर पर चीन के कस्टम आंकड़ों से मेल खाते हैं।
- 123. प्राधिकारी का यह मत भी है कि अन्वेषण के दौरान स्वीकृत सीआईएफ मूल्य के अनुसार आयातों का अवतरित मूल्य चीन कस्टम निर्यात मूल्य (डब्ल्यू टी ए आंकड़ों) से सह संबद्ध किया गया है और इससे मूल्य में उल्लेखनीय कमी हुई है और यह महत्वपूर्ण क्षिति मार्जिन दर्शाता है। चूंकि पाटन और परिणामी क्षिति पीओआई में जारी है, प्राधिकारी का मत है कि एडीडी वापस लिए जाने से संबद्ध देश से विचाराधीन माल के पाटन की पुनरावृत्ति होती है।
- 124. प्राधिकारी नोट करते है कि उन्हीं इच्छुक पक्षकारों ने अन्वेषण करने, विशेषकर जन सुनवाई करने के लिए निवेदन किया है। प्रक्रिया, प्रशासनिक होने के बजाय अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है, सहयोग के बाद चीन में आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, आदि। प्राधिकारी का मत है कि पूरा अन्वेषण एडी नियमों के अनुसार और प्रक्रियात्मक मुद्दों से संबंधित सतत परिपाटी अपना कर ही किया गया था। सहयोग न करने वाले उत्पादकों/निर्यातकर्ताओं के साथ संलग्न नियमों के अनुसार सख्ती से निपटा गया है। प्राधिकारी का मत है कि वास्तव में उन्होंने वर्तमान अन्वेषण में विभिन्न इच्छुक पक्षकारों के निवेदन पर

अत्यधिक विलंब से विचार किए जाने में उन्हें शामिल करने पर विचार कर आपवादिक काम किया है हालांकि इन इच्छुक पक्षकारों ने निर्धारित फार्म में मांगा गया उत्तर उपलबध नहीं करवाया था। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सभी संभव सिद्धांतों का संगत सीमा तक पालन करते हुए अन्वेषण किया गया है।

- 125. प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं जिसमें वे सभी गोपनीय निवेदन होते हैं जो इच्छुक पक्षकारों के संदर्भ के लिए रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षकारों द्वारा दिए गए होते हैं।
- 126. आयोग यह स्वीकार करता है कि पाटन रोधी ड्यूटी अधिरोपित की जाने पर भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटन रोधी उपायों के अधिरोपण से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन रोधी उपायों को अधिरोपित करने से पाटन परिपाटियों से प्राप्त किए जाने वाले अनुचित लाभ कम होंगे, घरेलू उद्योग के पतन से बचाव होगा तथा उपभोक्ताओं का विचाराधीन माल का अधिक विकल्प उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। इन उपायों से संबद्ध देश से किए जाने वाले आयात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामान्य तौर पर पाटनरोधी ड्यूटियों को अधिरोपित करने का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थित पुन: स्थापित की जा सके जो आमतौर पर देश के हित में है।

निष्कर्ष

- 127. उठाए गए मुद्दों, दी गई सूचनाओं और इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और इस निष्कर्ष में रिकार्ड किए गए तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों का ध्यान में रखते हुए तथा पाटन को जारी रखने की स्थिति के उपरोक्त विश्लेषण तथा परिणामी क्षति तथा पाटन एवं क्षति को जारी रखने/पुनरावृत्ति करने की संभावना के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- i चीन पी आर से संबंधित उत्पाद का पाटन लगातार बना रहता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- ii चीन पी आर से पाटित आयात के मूल्य कम होने और मूल्य से कम बेचे जाने के प्रभाव सकारात्मक हैं।
- iii चीन पी आर से पाटित आयातों के प्रभाव के कारण मूल्य में कमी होने से निवेश पर प्रतिफल, लाभप्रदता में कमी के रुप में घरेलू उद्योग की स्थिति बदतर हुई है। इन पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को लगातार हानि होती रहती है।
- iv यदि वर्तमान पाटन रोधी ड्यूटी वापस ले ली जाए तब भी चीन पी आर से विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी रहने/बढ़ने की संभावना है।

सिफारिशें

- 128. उपरोक्त निष्कर्ष निकालने के बाद प्राधिकारी का मत है कि पाटन रोधी उपाय का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि नीचे ड्यूटी टेबल में विनिर्दिष्ट किया गया है। प्राधिकारी द्वारा कम ड्यूटी नियम का पालन करने के संबंध में प्राधिकारी की सिफारिश है कि पाटन के मार्जिन और क्षति मार्जिन में जो कम हो उसके बराबर पाटन रोधी ड्यूटी अधिरोपित की जाए।
- 129. ड्यूटी संरचना के संबंध में मामले के तथ्यात्मक साँचे को ध्यान में रखते हुए तथा इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध करवाई गई सूचना और तथा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए एक पाटन रोधी ड्यूटी के निश्चित स्वरुप की सिफारिश की जाती है। तदनुसार सम्बद्ध देश में उत्पादित होने वाले या वहां आयातित होने वाले विचाराधीन माल के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा नीचे सारणी में दी गई राशि के बराबर ड्यूटी अधिरोपित करने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का	उद्गम का	निर्यात का	उत्पादक	निर्यातकर्ता	राशि	मापन	मुद्रा
		विवरण	देश	देश				की ईकाई	
1	29336100	मैलामाइन	चीन पी आर	चीन पी आर	कोई	कोई	331.10	एमटी	अमेरिकी डालर
2	29336100	मैलामाइन	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से इतर कोई अन्य देश	चीन पी आर	कोई	कोई	331.10	एमटी	अमेरिकी डालर
3	29336100	मैलामाइन	चीन पीआर	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देशों से इतर कोई अन्य देश	कोई	कोई	331.10	एमटी	अमेरिकी डालर

130. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त नियम की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 और 9 क के अंतर्गत शुल्कों को छोड कर समस्त सीमा शुल्क शामिल होंगे।

आगे की प्रक्रिया

- 131. केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद आदेश के विरुद्ध अपील कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण को की जाएगी।
- 132. प्राधिकारी अधिनियम, नियमों और इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए सार्वजनिक नोटिसो के संगत प्रावधानों के अनुसार यहां अनुशंसित उपायों को जारी रखने, उनमें संशोधन करने या परिसमापन करने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं। ऐसी समीक्षा के लिए किए गए किसी अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक इच्छुक पक्षकार द्वारा इस प्रयोजन से निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुरोध न किया जाए।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2015

Final Findings (Sunset Review)

Subject: Sunset Review of Anti-Dumping duty on imports of 'Melamine' originating in or exported from China PR

No 15/17/2014-DGAD: - Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the case

- 2. Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had recommended imposition of provisional duty on imports of Melamine originating in and exported from China PR vide notification No.14/16/2003-DGAD dated 27.02.2004 and such provisional duty was imposed by the Government of India vide Notification No.53/2004-Customs dated 02.04.2004. The Authority issued its final findings recommending imposition of definitive anti dumping duty on imports of Melamine (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country), vide notification No. 14/16/2003-DGAD dated 03.09.2004 and such definitive duty was imposed by the Govt. of India vide customs notification No. 107/2004-Customs dated 16th November, 2004.
- 3. Whereas, the Designated Authority thereafter vide notification No. 15/29/2008- DGAD, dated the 21.11.2008, had initiated sunset review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of subject goods, originating in, or exported from, the subject country. The Designated Authority vide notification No. 15/29/2008-DGAD, dated the 20.11.2009, had recommended for continuation of the anti-dumping duty. Notification No. 10/2010-Customs was issued on 19.02.2010 imposing anti dumping duty on imports of Melamine from the subject country.
- 4. Whereas, M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd has filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, extension of period, modification and enhancement of existing anti dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
- 5. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a Sunset review investigation vide Notification No 15/17/2014-DGAD dated 09.12.2014 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry

B. Procedure

- 6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority sent copy of the initiation notification dated 9th December, 2014 to the embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country and known importers, as per available information. The known interested parties were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassy of the subject country along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.
- ii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicant was made available to the known exporters and the embassies of the subject country in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- iii. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review to the following known producers/exporters in the subject country and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules:
 - a) China Huaya Group Co. Ltd
 - b) Yingkou Tianyuan Elaborate Chemical Industry Co., Ltd
 - c) Inner Mongolia Ihjuchem Industrial Co., Ltd

- d) Naier chemical Co. Ltd.
- e) Henen Harvest International Co. Ltd.
- f) Henan Hongye Chemical Co. Ltd
- g) Golden Elephant Chemical Co. Ltd
- iV. In response to the initiation of the subject investigation, none of the producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response
- V. Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to the known producers/ exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation, the normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it holds to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers in China PR. However, none of the producers/exporters from China PR have filed MET questionnaire response rebutting the non-market economy treatment to China PR.
- vi. Questionnaires were sent to the following known importers/users/associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules:
 - a) Greenply Industries Ltd
 - b) Merino Industries Ltd.
 - c) Merino Panel Products Ltd
 - d) Golden Laminates Ltd
 - e) Surya Vikas Plywood Pvt. Ltd
 - f) Katyani Chemtech India Ltd
 - g) Rushil Décor Ltd
 - h) Sundek India Ltd
 - i) Bloom Dekor Ltd
 - j) HEF India Private Ltd
 - k) Century Plyboards India Ltd
 - 1) Managlam Timber Products Ltd
 - m) Virgo Industries
 - n) Alfa Ica Ltd
 - o) The Bombay Burmah Trading Co
- vii. In response to the above notification, following importers have filed questionnaire response through M/s Ernst & Young LLP
 - a) Meghdoot Laminart Pvt. Ltd.
 - b) Century Plyboards (I) Ltd.
 - c) Bloom Dekor Limited
- viii. Further, the Laminate Manufacturers Association has filed response to the petition through M/s Ernst & Young LL.P.
- ix. M/s. Sandeep Organics filed submissions on 28th January, 2015 but did not file importer's questionnaire response. Further submissions were made vide email dated 20th October, 2015. The company did not participate in the oral hearing despite the notice of hearing served to them by the Authority.
- X. M/s. Balaji Action Buildwell (through ITS Legal Advocates & Consultants) and M/s Exim Corp did not register themselves as interested parties within the stipulated time nor did they file any importer questionnaire response within the stipulated time but filed belated submissions only in October 2015. Thus, the parties have not availed opportunity provided to them in timely manner. M/s. Balaji Action Buildwell desired to inspect the public file. The Authority notes that the company has not registered itself as an interested party and did not file any submissions/data on imports made by them. The Authority notes that anti-dumping duty investigations being time bound, require exchange of submissions being filed by registered interested parties and file comments, in order to assist the authority to arrive at a fair determination. In case of M/s. Balaji Action Buildwell, the

- Authority notes that despite the fact that company did not cooperate in the investigation for 10 months and has approached the Authority only at the 11th month of investigation, the Authority taking a pragmatic view has however, decided to consider and dealt with their submissions appropriately. The submissions of M/s Eximcorp have also been dealt with appropriately.
- xi. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating.
- xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and also DG Systems, Ministry of Finance to arrange for details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, however, relied upon the DG Systems imports data for computation of the volume of imports and injury analysis for investigation for the reasons as enumerated below in this finding.
- Xiii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure II to the Anti-dumping Rules.
- Xiv. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April, 2013 to 30th June, 2014 (15 months). However, injury analysis covered the periods April, 2010-March, 2011, April, 2011-March, 2012, April, 2012-March, 2013 and the POI.
- XV. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 28th September, 2015. The parties, who presented their views in oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- XVi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been considered by the Authority, wherever found relevant, in this finding.
- XVii. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry.
- XVIII. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- XIX. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- XX. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 23rd November 2015, to the known interested parties and comments received on the same, to the extent considered relevant by the Authority, has been considered in this final finding.
- XXI. "-**" represents information furnished by an interested party/ other party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- XXII. The average exchange rate of 1US\$ = Rs 60.64 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this finding.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

7. The product under consideration in the present investigations is Melamine. In the original case, the Final Findings issued via Notification F.No. 14/16/2003-DGAD, dated 3rd September, 2004 defined the product under consideration as follows.

"Product under consideration in the present investigation is Melamine, a tasteless, odorless, and non-toxic substance. Melamine is used for making melamine formaldehyde, which in turn is used in producing downstream products. Melamine formaldehyde resin used for laminates offer good hardness, resistance to scratch, stain, water and heat.

Melamine has a dedicated Custom Sub Heading 29336100 of Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product falls under OGL category and is freely importable."

- 8. Since the present investigation is for sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as that of the original investigation. The product under consideration, Melamine, is classified under Chapter 29 under subheading 29336100. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
- 9. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

- 10. The application filed is for the review, continuation and enhancement of the quantum of the anti-dumping duty in force, and the issue of like article has been already dealt with in the previous investigations. In the earlier investigations the Authority has already held that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the subject goods imported from the China PR
- 11. As regards the argument of different grades of product under consideration, it is noted that none of the exporters of the product under consideration cooperated or provided any information regarding different grades of product under consideration.
- 12. There is no significant difference in the Melamine produced by the Domestic Industry and the Melamine exported from China PR. Melamine produced by the domestic industry and exported from China PR are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing. Even though there are different manufacturing process/technologies involved for production of Melamine, the end product has comparable specifications and is used interchangeably. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used the two interchangeably. Melamine produced by the domestic industry and imported from China PR has been treated as like article in accordance with the Anti-Dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

- 13. The application for the sunset review has been filed by M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. As per the information available, the petitioner company is not related (neither directly nor indirectly) to any exporter in the subject country or importer of product under consideration in India. The petitioner has not imported the subject goods from subject country during period of investigation. However the petitioner has made some imports from subject country during the base year. The Authority is of the view that the focus of the company continues to be of a producer and do its own production. The company is therefore held to be domestic industry within the meaning of the Rules.
- 14. The petitioner company is the sole producer of the product under consideration in India. The Authority after examining the information on record has determined that the petitioner company constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

E. <u>Other Issues</u>

Submissions made by the Exporters/Importers/users/other Interested Parties/ other parties

- 15. Following submissions have been made by the exporters/importers/ users/other interested parties/ other parties
 - i. Authority has relied on DGCIS data for determination of export price as it is a government source rather than a private data source. A report by the Ministry of Chemicals and Petrochemicals on the imports of the subject goods in the most recent period exhibits a much higher import price as compared to even the DGCIS data.
 - ii. As regards Domestic Industry's submitting an Alert Circular issued by the DRI, it is stated that that this Alert is merely to make the field formations aware of such a practice; however it is not a blanket and conclusive finding on all import transactions concerning the subject goods. It is not an acknowledgement that the import prices are necessarily being manipulated by importers but merely a warning to the field formations to be careful about potential manipulation of the import prices with an intent of avoiding anti-dumping duty.
- iii. The sanctity of import transactions which are subject to the control and surveillance of the customs is unwarranted. If at all any complaint has to be made challenging the mechanism of customs procedures which allegedly failed to check fictitious import transactions, the complaint must be lodged with the appropriate forum, that is, the Department of Customs. To challenge the accuracy of imports data alleging that the import prices are fictitious tantamount to questioning the database or information of the DGCIS which been considered as accurate and reliable by the Authority in several anti-dumping investigations.
- iv. Initiation Notification is not based on duly substantiated application and that on basis of fair and objective examination of the evidence.
- v. The applicant has forwarded its information in the pro-forma, which is actually meant for the original application and not for SSR investigation. This has led to an anomalous situation as the kind of information that is required in an original investigation is simply not suitable for the kind of analysis that is required to be undertaken by the Authority in a SSR investigation
- vi. Neither the initiation notification is based on suo motu basis; nor is there a duly substantiated application before the Hon'ble Authority, to justify initiation of the instant investigation

- vii. The imports under advance license/authorisation are squarely governed by the Standard Input output norms as per the Foreign trade Policy
- viii. There is a huge demand and supply gap so far as the subject goods is concerned. However, despite the existence of significant demand, the domestic industry claims to have linked its prices with that of the imported goods. Imports under the advance license mechanism which are not meant for sales in the Indian domestic market at all and not in any competition with the domestic sales made by the domestic industry.
- ix. 1/3rd of the imports have been made admittedly under the duty-free schemes that do not attract anti-dumping duty and 2/3rd of the imports have been made at above the reference price of \$ 1400, thereby meaning at undumped prices. If the import price were fictitious the domestic industry ought to have filed Mid-term review
- x. As regards reference price duty being ineffective, then the domestic industry ought to have filed Mid-term review application for change in quantum and form of duty. No evidence have been provided by the domestic industry to substantiate the claim.
- xi. Chinese customs data would also include those transactions that have been made under the duty-free mechnasim, which do not attract anti-dumping duty and therefore must be excluded from the ambit and scope of both dumping and injury analysis. Whereas for the purpose of injury analysis, landed price would be required, which is already available in the form of Bill of entries data

Submissions made by Domestic Industry

- 16. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry
 - i. The DRI finding is conclusive in nature and Designated Authority cannot ignore the findings of other Government department. Based on the DRI investigation, Customs department found that certain importers were indulging in overvaluation of Melamine, imported from China in order to avoid payment of anti-dumping duty leviable on such imports. DRI, after conducting investigation, submitted in its finding that the importers are overvaluing the product to evade anti-dumping duty.
- ii. The domestic industry has given detailed reasoning with the supporting evidence for finding of DRI to prove that the price stated in the import data is fictitious price and not the actual one.
- iii. The DGCI&S average import price cannot be considered for the reasons well explained in the petition and written submissions.
- iv. The petition clearly shows positive price undercutting. The statements in the Annual Report are with regard to deterioration in performance of the domestic industry for a year. The Annual Reports are however focused only on the period under consideration. The Designated Authority is concerned with performance of the domestic industry over the injury period. Designated Authority's decision is not based on POI alone. Designated Authority's decision is based on performance over injury period.
- v. Imports under advance license are causing injury to the domestic industry. The imports entering in the Indian market under advance license are the imports which are governing the price of the domestic industry and market as a whole. Import for export production are exempted by the Govt. of India from purview of anti dumping duty under advance authorization scheme does not imply that these imports are not causing injury. It only implies discretion of the Govt. of India while imposing anti dumping duties.
- vi. Domestic Industry has filed detailed reasoning as to why either imports under Category I or China customs data should be adopted to determine import price.

Examination by Authority

- 17. The Authority notes the submissions made by the various interested parties/ other parties on actual price of imports of product under consideration into India. The domestic industry argued that import price as per Indian customs is not the actual price and therefore requested to adopt either price as per China Customs or the price of imports under advance license. To support their argument the Domestic Industry has provided an Alert Circular by DRI wherein DRI had found that certain trader importers were declaring higher values in comparison to the import value of actual user importer. The opposing interested party argued that DRI alert letter is merely to make the field formations aware of such a practice; however it is not a blanket and conclusive finding on all import transactions concerning the subject goods and the sanctity of import transactions which are subject to the control and surveillance of the customs is unwarranted and therefore DGCI&S data should be adopted by the Authority for determination of volume and value of imports.
- 18. As regards the argument that Authority can only rely on DGCI&S data and not on a private source or other source, the Authority notes that in the past it has adopted private source data and also China Customs for determination of volume and value of imports after appropriate correlation of facts keeping in view the nature of data, its availability,

context and reliability. The adoption of IBIS data at the time of initiation, for determination of volume of imports is also consistent with the past practice of Designated Authority.

- 19. As regards determination of import price, the Authority noted the details of investigation conducted by DRI and requested information from DRI with regard to the actual value of imports determined by them so as to conduct dumping and price effect analysis.
- The Authority, therefore, noting the submissions made by various interested parties on referencing different sources of import data for volume and price of the imports product under consideration, holds that in the past it has adopted various data sources appropriately to the extent of details available in a data source, its reliability and context as stated above and to the extent possible, ensures correctness of various secondary source data with inter se correlation amongst various sources and also responses filed by cooperating exporter/importer. In the instant case, the Authority has considered data from DGCI&S as well as DG Systems. Further, the Authority, based on the submissions of the domestic industry on the alert circular issued by DRI, obtained relevant details from DRI on the alleged circumvention of the anti-dumping duty by certain traders /importers. The Authority correlated the data obtained from DGCI&S, DG Systems and China Customs and the information obtained from DRI. The Authority notes that the quantity of imports of product under consideration as per DGCI&S, DG Systems and China Customs broadly correlates. As no exporter of the product under consideration from subject country has responded and only three importers with total imports of 645 MT have provided data, therefore the price as per the importer's questionnaire response would not be reflective of the total imports of the product under consideration. As per DG Systems data, the Authority notes that there is a wide variation in the import price under duty free imports and non duty free imports. The Authority notes that this is occurring despite the fact that the import product is same under both the routes. The DRI's alert circular and the information provided by DRI to the Authority evidence non- reliability of the import price of non duty free imports when compared to the advance license prices during the POI. Further, the Authority examined the overall imports price as per China Customs data and the import price of duty free imports as per DG Systems data and observes that the prices broadly correlate. Further, the investigation conducted by DRI so far also corroborates the reliability of these two prices. Therefore the Authority holds that adoption of import price of duty free imports as per DG Systems data for both dumping and injury determination is fair and appropriate.
- 21. As regards the contention that Applicant has not filed a 'duly substantiated' petition in terms of Rule 23(1B) of the Anti-Dumping Rules by providing sufficient and accurate information, the Authority notes that the present investigation was initiated on the basis of sufficient prima facie evidence furnished by the domestic industry showing dumping, injury and causal link and the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and justifying initiation of the investigation in accordance with the Act and Rules. The data as available at this stage upholds the correctness of the approach adopted at the time of initiation.
- 22. With regard to exclusion of imports under advance license for dumping and injury determination, it is noted that these imports have been taken into account for the purpose of working out dumping and injury as these dumped imports adversely affect the opportunities available to domestic industry to increase their supplies to these exporters and to that extent, the demand of the subject goods declines. It is noted that it is the consistent practice of the Authority to include imports under duty exemption for the purpose of assessment of injury to the domestic industry.
- 23. With regard to form of duty and alleged over invoicing, the Authority has considered the facts of the present case for deciding an appropriate form of measure.

F. <u>MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN</u>

Submissions made by exporters, importers and other interested parties/other parties

- 24. Following submissions have been made by the exporters, importers and other interested parties/other parties with regard to normal value, export price and dumping margin
 - i. India cannot be considered as surrogate country for determination of normal value for China because (a) The scale of operations of producers in China is much larger as compared to producers in India. (b) Production capacities of manufacturers in China are significantly higher than that of the Applicant. (c) The cost of production of the subject goods in China is much lower than that in India as a result of economies of scale. (d) China produces its Melamine by use of Coal Gas which is cheaper and more efficient as compared to Urea which is used in India.
- ii. The construction of the normal value is impermissible and the export value has been incorrectly calculated, the Authority must disregard the consequent dumping margin computed by the DI.
- iii. There are a number of judicial proceedings pending against the Applicant for use of natural gas procured at APM prices for production of products other than fertilizers. In particular, the proceedings relate to the illegal use of natural gas procured at APM prices for production of products such as Melamine. Use of the Applicants data is not suitable or appropriate for construction of normal value.

Submissions made by Domestic Industry

- 25. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry.
 - i. China is a non-market economy. It has been treated so by European Union and United States in the past. No country has granted market economy country status to China after following detailed evaluation procedure and examination. In India also, the Designated Authority has treated China as non-market economy. In practically all the investigations initiated against China after the amendment dated 31st May, 2002.
- ii. AD Rules have prescribed certain conditions that have to be satisfied in order to establish the claim of market economy treatment. Each and every condition must be fulfilled by an intending exporter in order to claim market economy treatment.
- iii. In the present case, Normal Value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available.
- iv. The Domestic Industry has relied upon the IBIS data to assess the volume and value of subject import in India. However, IBIS provides import value as assessable value. According to the WTO Agreement on Anti Dumping and Indian Rules, comparison of normal value and export price should be done at same level of trade. Therefore, the export price has been adjusted for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Port Expenses, Bank Charges, Inland Freight Expenses and VAT adjustments.
- v. The dumping margin is above de minimus and is significant, despite existing duties.
- vi. The Normal value estimated, has been artificially contrived upwards to achieve the domestic industry's self-serving objective to somehow continue to garner the benefits of antidumping.

Examination by Authority

- 26. Under section 9A (1) (c), the normal value in relation to an article means:
 - (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
 - (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):
 - Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of exporter there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.
- At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters have filed any response.
- 28. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.
- 29. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:

- a. the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b. the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c. such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and
- d. the exchange rate conversions are carried out at the market rate.
- 30. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority, none of the Chinese companies have filed exporter's questionnaire response. Therefore, the Authority is not in a position to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules to the Chinese companies and has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules. According to these Rules, the normal value in China PR can be determined on any of the following basis:
 - a. On the basis of the price in a market economy third country, or
 - b. The constructed value in a market economy third country, or
 - c. The price from such a third country to other countries, including India.
 - d. If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.
- 31. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. Since no information with regard to prices and costs prevalent in these markets could be accessed and also the opposing interested parties have provided no information with regard to an appropriate market economy third country, the normal value in respect to China PR has been worked out on other reasonable basis, in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. Thus, the Authority determines to construct the normal value for the product under consideration imported during the POI from China as follows:
 - (a) The best utilisation norm of the raw materials based on the best information available has been considered.
 - (b) Cost of utilities, conversion cost, SGA expenses and interest have been considered on the basis of the best information available.
 - (c) 5% of cost of sales excluding interest has been allowed as a reasonable profit.
- 32. Accordingly, the Constructed Normal Value computed at ex-factory level has been determined as US\$ *** per MT (Rs.*** per MT).

Export Price of Subject Country

- 33. As none of the exporters of the subject country has provided any information that can be used for determination of the export price, the Authority holds to determine the export prices for all exporters from subject country on the basis of CIF price of duty free imports into India as per DG Systems data, duly correlated with the export prices of China customs data. The Authority while adopting this approach keeps in mind the findings of DRI's investigation on circumvention of ADD under non- advance license imports and the disclosure of prices by traders/ importers of PUC from China PR and voluntary deposition of ADD by them, which renders the import prices of the PUC under non duty- free route as unreliable.
- 34. Accordingly, export prices from the China PR are calculated on the basis of CIF price of product as stated in para 33 above with applicable adjustments for Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Commission, Inland transportation and Bank Charges, have been made to arrive at the ex-factory export price. Accordingly, the net export price has been determined as US\$ *** per MT (Rs.*** per MT).

Determination of Dumping Margin

35. Considering the normal values and net export prices as determined above, dumping margins are determined as follows:

Units	China PR (POI)
US\$/MT	***
US\$/MT	***
US\$/MT	***
%	***
% Range	40%-50%
	US\$/MT US\$/MT US\$/MT

36. The above evaluation indicates that the subject goods continue to enter the Indian market, from China PR, at dumped prices and that the margin of dumping is quite significant.

G. <u>METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK</u>

Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties/other parties

- 37. Following are the submissions made by exporters, importers and other interested parties/other parties:
- i. Applicant's production has increased by 7% in the POI as compared to 2010-11. Capacity utilization has not decreased even though there is increase in the capacity. In particular, the capacity utilization shows an increase as against the base year and as against the immediately preceding year.
- ii. A company that is allegedly suffering injury would not be in a position to increase its capacity. Therefore, the data relating to production, capacity, capacity utilization and inventory do not indicate any injury caused to the Applicant.
- iii. The sales of the DI have increased significantly in POI registering a growth of 15.3%. In addition, the sales value has also increased.
- iv. Decrease in the market share is due to the fact that it did not have the capacity to increase its production of the like product as it utilized its full capacity. The domestic industry failed to meet the domestic demand; the domestic users of the like product were compelled to fulfill their requirements by imports. It is highly unjust on the part of the Applicant to blame imports from the subject country for the decline in the market share of the domestic industry
- DI has been able to maintain a low level of inventories. In fact inventories have not increased and have rather declined till the POI.
- vi. Employment, productivity and wages will definitely be impacted if dumping has the effect of injuring the domestic industry. The wages have consistently increased every year of the injury period and the POI. In addition, even the employment has increased over the injury investigation period. Were the Applicant truly suffering injury, it would have no reason to increase employee wages and moreover, continue to hire additional employees. On the converse, an industry that is facing injury or threat of injury would be expected to lower wages and/or downsize its employee base. The productivity has also increased.
- vii. There is no price undercutting as per data of DGCI&S. As per page 53 of 52nd Annual Report 2013-14 the Applicant's total Melamine sales was Rs. 13,920.61 lacs for 2013-14. Further, as per page 23 of the 52nd Annual Report, the Applicant has sold 15,378 MT of the like product during 2013-14. Thus, unit selling price of the like product works out to Rs. 90,520 per MT. Request the Authority to consider the above calculation relating to price undercutting which is based on DGCIS's import data
- viii. The underlying reason for not levying anti-dumping duty on imports under advance license is to promote exports from India and therefore any imports covered under the advance license must not be regarded as inflicting injury to the domestic industry. It will therefore be grossly incorrect to consider imports of the PUC under advance license for the purpose of computing price undercutting as claimed by the Applicant.
 - ix. There has been an increase in the selling price as well as the cost of sales. An increase in the cost of sales has in turn resulted into an increase in the selling price of the subject goods. The selling price has been increasing consistently over the years as per the Annual Reports of the DI for 2013-14, 2012-13 and 2011-12. The consistent increase in the selling price of the like product cannot be denied on any premise, as it is fully evident from the published Annual Reports of the Applicant.
 - x. The landed price of imports from the subject country increased by 29% in the POI as compared to the base year. The landed value of imports from China in the POI was 7% higher than the selling price of the DI.
- xi. The selling price of the Applicant is and has been increasing and there has not been any price undercutting. Therefore, the imports from the subject country has not at all contributed to the loss being suffered. Any losses suffered by the Applicant can only be explained by certain extraordinary expenses.

- xii. The Applicant's Annual Report for 2013-14 provides that there have been higher dependence on imported raw materials viz. Ammonia and from countries in Middle East and Africa where political unrest had impacted the supply chain and that too to an extent affecting GSFC's production and profitability. In addition, depreciation of rupee against USD increased the cost of production of fertilizers as well as imports. Applicant's expenses such as power and fuel, depreciation, wages, finance cost and other expenses have increased significantly during the injury period. The Applicant could have certainly earned profits and any losses (net profits) or declining return on investment it suffered was exclusively on account of significant increase in expenses such as other expenses, depreciation and wages.
- xiii. As there is no existing injury, the possibility of continuation of injury, under Article 11.3 of the WTO ADA and Rule 23(1B) of the Indian AD Rules, is ruled out and not relevant in the present investigation.
- xiv. India is not a key market for exports from China. In particular, only 11.3% of the total exports of subject goods from China are exported to India. The exports to India have rather decreased. An increase in exports of the subject goods from China is unlikely regardless of the capacities of Chinese exporters. The data pertaining to total capacities of Chinese exporters relates to its production capacity for the Chinese markets as well as to markets across the world.
- xv. The existence of large capacities in itself does not demonstrate that dumping would be probable or likely. In fact, the existence of large capacities in China has no bearing on the likelihood of dumping in India particularly when evidence demonstrates that the exports from China are destined for other markets where drastic increase in exports have been witnessed and exports to India have rather decreased.
- xvi. Even after imposition of duty for 10 years, there has been no improvement in its performance, it is clear that the DI has been suffering any alleged injury as a result of its own inefficiencies. The fact that the reason for decline in its profits and return on investment is as a result of expenses that are intrinsic only to the DI.
- xvii. The present positive performance of the Applicant, which is evident from the improvement on all the key injury parameters, has resulted from its own strategic decisions such as increase in capital investments and capacity.
- xviii. Despite the continued injury, the domestic industry has thought about expanding just now and it has never sought to move a Mid-term review application seking modification and enhancement of the anit-dumping duty in forece.
- xix. the imports must be seen in the context of huge demand and supply gap. Undoubtedly, the imported goods must come in at undumped prices, which precisely has been happening in the present matter, once we exclude the transactions that have been made under the duty-free mechanism.
- xx. the Applicant has failed to provide "positive evidence" that establishes that dumping and consequent injury would be "probable" if the duty is terminated.
- xxi. that the injury margin that is determined by the Hon'ble Authority must take into consideration the 'landed value' of only those transactions that have not been made under the duty-free schemes. Besides, it must take into account the conversion rate (of Dollars to Indian Rupees) when the goods have been cleared.
- xxii. Applicant has enjoyed the benefits accruing to them by virtue of the continued imposition of Anti-dumping duties for really a long time (for over 10 years) and now again seek its further continuation for another period of 5 years. The anti-dumping duties must not continue, as India has taken an in-principle stand before the WTO not to extend the measure beyond a period of 10 years.
- xxiii. M/s GSFC has capacity of 15,000 ton per annum and has planned for increase.
- xxiv. It is incurring expenses on know- how technology as well as on technology selection process;
- xxv. Consumption of power has increased whereas consumption of steam and gas has decreased;
- xxvi. Production, sales and stock in trade have increased whereas inventory has decreased. Trading has resulted in increase from Rs. 1179.11 lakhs in 2013 to Rs. 2010.08 in 2014. Foreign exchange earned is Rs. 15.18 lakhs in the year 2013-2014.
- xxvii. There is difference in quality. Nitrogen and coal are raw material in Chinese material;
- xxviii. GSFC is importing melamine and trading;
- xxix. There are many grades with regards to quality;
- xxx. GSFC is government backing company and enjoys privileges and is also in monopolistic situation. The duty is 12.36 in GSFC. The DGAD is requested to take into account the number of shut downs in GSFC and GSFC's capacity, demand and supply and also of the fact that there is new management in GSFC recently;

- xxxi. The DGAD is requested by M/s Sandeep Organics to provide it non- confidential version submissions made by all parties;
- xxxii. The DGAD is also requested to issue Preliminary Findings & call for oral meeting before Final Findings;
- xxxiii. The duty is 1% landing cost, 2% cess, 1% cess, 7.5% basic duty, 12% custom duty & 4% special additional duty;
- xxxiv. It charges 2% CST and freight for out station sales which add to the cost to the buyer, but there is no CST and freight in imports;
- xxxv. It doesn't give credit to buyers and incur commissions & incentives to agents;
- xxxvi. Already there is AD duty from past 11 years and same flexible AD duty should be continued;
- xxxvii. Disclosure statement should be provided to M/s Sandeep Organics and Preliminary Findings should be issued before Final Findings;
- xxxviii. ICIS report should not be considered as it is a private & commercialised report;
- xxxix. China export data should not be considered and Indian import data should be considered;
 - xl. Fluctuation in raw material ammonia, coal, urea, natural gas & fertilizers as well as in wood panel & adhesive should be considered:
 - xli. Fluctuation in crude & currency (USD- INR & RMB- INR) should be considered;
 - xlii. DRI investigation is not concluded;
- xliii. There is AD duty on imports from other countries;
- xliv. Many China factories are closed now;
- xlv. Quality of china is very inferior;
- xlvi. Recently imports have decreased and the domestic industry has raised prices;
- xlvii. The domestic industry faces problems of frequent shut down and is importing & trading;
- xlviii. Domestic industry is government controlled & gets subsidy. It is not professionally managed and is giving vague reasons of imports. There is non capitalisation of resources by it;
- xlix. It faces raw material & electricity shortage problem, and the machines are also old;
 - 1. Now imports under DFIA is also stopped making imports not viable;
 - li. Customs is passing Chinese cargo after paying ADD;
 - lii. There is 4% special additional duty on import and 2% central sales tax in the domestic industry;
- liii. There is no domestic industry as M/s GSFC Ltd, the importer- producer of the subject goods is the sole domestic producer;
- liv. The methodology followed by DGAD while recommending the duty table is flawed as by converting the NIP to US Dollars, a serious distortion has been created to confer windfall gains on domestic industry;
- lv. The quantum of AD duty on market economy exporters must not exceed the amount of ocean freight involved as any constructed cost for the exporter is a fallacy on presumptions which are not validated;
- Ivi. When there are so many grades of domestic producer, the weighted average sales realisation is not fair. Domestic grades must be correlated to the correspondent grade of the imported melamine in order to draw a fair comparison;
- lvii. The injury to domestic industry from factors other than dumping must be quantified and separated before arriving at any fair comparison;
- Iviii. There exists a situation of dumped imports not sold in India on dumped prices. DGAD doesn't have a practice to exclude such dumped imports not on dumped prices. This violates the restrictions and prohibitions under ADA and AD Rules.

SUMBISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

38. Following are the submissions made by the domestic industry in this regard:

- i. The apparent consumption of the subject goods has increased throughout the injury period. Market share of domestic industry has slightly increased 2011-12 from the base year and then declined thereafter. The market share of imports from China has increased throughout the injury period.
- Imports from subject country have substantially increased in spite of Anti-dumping duty in existence in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
- iii. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry.
- iv. Imports are suppressing the domestic prices.
- v. Performance of the domestic industry deteriorated in terms of profits, return on investments, cash flow. Consequent impact of dumping on the domestic industry has been significantly adverse.
- vi. The domestic industry suffered huge financial losses despite anti-dumping duties in existence only due to continued dumping and form of duty. With significant dumped imports entering the Indian market, the domestic industry, in order to sustain in the market, were left with no option but to sell the goods at sub-optimal prices. The domestic industry was prevented from raising its prices in proportion to increase in costs.
- vii. In view of the demand supply gap of Melamine in the country, the petitioner is in the process of expansion wherein the company plans to expand its capacities further by 40,000MT. However, in view of the significant dumping and consequent injury to the domestic industry, in the event of the revocation of the anti-dumping duty, the expansion plans for the domestic industry would be significantly affected.
- viii. Given the level of price undercutting, it is evident that the demand for the imported product would substantially increase in the event of revocation of anti dumping duties. This would directly imply decline in the demand of the domestic industry product, which is likely to result in decline in production of the domestic industry.
- ix. Domestic Industry has not claimed volume injury rather claimed price injury, which is clearly established by the decline in profits, cash flow and return on investment. Considering the level of price undercutting, it is evident that the demand for the imported product would substantially increase in the event of cessation of anti dumping duties.
- x. Capacity enhancement is long term decision and the domestic industry in this case has taken steps to enhance the capacity in order to meet the demand of the users.
- xi. If the exporters want to supply the goods to meet the requirement in Indian market that could be done by exporting the goods at normal value and not at dumped prices. There is no bar in imposing anti-dumping duty if there is demand supply gap.
- xii. Domestic Industry has not claimed injury on account of inventories but injury in the form of profits, return on investment and cash flows.
- xiii. Domestic Industry has not claimed injury on account of wages, employment and productivity. The Domestic Industry being a Government Company cannot hire and fire the employees as and when required.
- xiv. Domestic industry was compelled not to increase their price in proportion to increase in cost of sales thereby suffering huge losses. Increase in the selling price was never disputed.
- xv. The Domestic Industry uses its own Urea for manufacturing of Melamine and there is no shortage of the same. Wage cost has declined since base year. Extraordinary expenses have been excluded from injury analysis.
- xvi. Domestic industry has been significantly adverse owing to Dumping. Imports from subject country have substantially increased in spite of Anti-dumping duty in force. These imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry and suppressing the domestic prices.
- xvii. The nameplate capacity in China for melamine is around 1.8m tones/year against the consumption of around 1m tones/year which meant the average plant operating rate is at 50-60%. Therefore in the event of cessation of anti-dumping duty, the exporters from subject country would export to India in huge volumes in order to improve their utilization. Further, the oversupply in China forced their major producers to seek more exports to overseas markets to cope with poor local demand.
- xviii. The importers are resorting to overvaluation in order to evade anti-dumping duty and benchmark form of duty has remained ineffective. Therefore it is all the more reason to extend the anti-dumping duty with enhanced quantum and fixed form.
- xix. Requested the authority to consider, for the purpose of assessing injury, the Non APM price of natural gas for determining cost of ammonia which is required for the production of urea which is in turn required for the production of Melamine. Natural gas made available to the company at pre-determined price by the Government for eventual production of fertilizer is wholly irrelevant for the purpose.

- xx. The dumping margin with respect to the subject country in previous investigation as well as present investigation is not only above de minimus but also substantial.
- xxi. European Union has imposed anti-dumping duty against the imports of subject goods from subject country. The exporters from subject country are habitual to dumping practices since many years and have been dumping not only into India but also to third country. The dumping is likely to continue in India as well in the event of revocation of anti dumping duty on imports of subject goods from subject country.
- xxii. volume of imports in case of subject country have significantly increased despite imposition of anti dumping duty. When the imports from subject country are showing the increasing trend even in the presence of anti dumping duty, there are all the probabilities that the volume would increase in the event of revocation of anti dumping duty.
- xxiii. Producers in subject country maintain huge capacities to produce subject goods.
- xxiv. Imports from subject country are likely to undercut the prices of the Domestic Industry in the event of revocation of anti-dumping duty. The price undercutting is likely to force the Domestic Industry to reduce its prices further.
- xxv. The Chinese producers are exporting huge volume of subject goods to third countries at dumped prices.
- xxvi. DRI after conducting investigations against imports of product under consideration came to the conclusion that importers of the product under consideration are importing the product by overvaluing it in order to evade anti-dumping duty. It is apprehended by the petitioner that if such practices of duty evasions are prevailing when anti-dumping duty in force, there is a strong likelihood that in the event of cessation of anti-dumping duty, the dumped imports from subject country would enter the Indian market at significant volumes.
- xxvii. The market share of Chinese imports is quite significant in spite of the existing anti dumping duties. In fact the market share of the imports has increased over the years and that of domestic industry have declined.
- xxviii. the exporters from the subject countries have very high export orientation worldwide.
- xxix. The price undercutting without prevailing anti-dumping duties is positive.
- xxx. The import prices are materially below selling price of the domestic industry. The consumers would therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.
- xxxi. The domestic industry is already suffering price suppression due to dumped import prices which are even below cost of sales of the domestic industry. In case of revocation of anti-dumping duty, the domestic industry shall have to reduce their selling price further to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales; leading to severe price injury.
- xxxii. The reference form of anti dumping duty has been ineffective in preventing dumping.

Examination by the Authority

- 39. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
- 40. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree. 31.
- 41. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure-II of the Antidumping Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

- 42. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.
- 43. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
- 44. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from China PR are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing antidumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.
- 45. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

Volume Effect

Demand and market share

Particulars	Units	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Annualized POI
Demand						
China PR	MT	17,580	16,718	19,095	30,780	24,624
Countries attracting ADD	MT	11,976	12,222	15,443	16,339	13,071
Other Countries	MT	731	1,797	5,861	6,741	5,393
Domestic Industry	MT	13,319	15,284	14,022	18,537	14,830
Other Indian Producers	MT	-	-	-	-	-
Total Demand	MT	43,606	46,021	54,422	72,397	57,918
Market share						
China PR	%	40.31	36.33	35.09	42.52	42.52
Countries attracting ADD	%	27.46	26.56	28.38	22.57	22.57
Other Countries	%	1.68	3.91	10.77	9.31	9.31
Domestic Industry	%	30.54	33.21	25.77	25.61	25.61
Other Indian Producers	%	-	-	-	-	-

- 46. The Authority has considered the transaction-wise import data provided by DG Systems for the assessment of volume and value of imports from the subject country and other countries. Demand for the product under consideration has been determined as the imports of the product under consideration into India from all countries and sales of all domestic producers in India.
- 47. The Authority notes that demand for the subject goods has shown consistent increase over the injury period. The above data indicates that the market share of the domestic industry has increased during 2011-12 but declined thereafter. The market share of China PR has increased consistently.

Import volumes and share of subject country:

48. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti-dumping rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India".

49. The import volumes for the injury period are as under:

Particulars	Units	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Annualized POI
Imports Volume						
China PR	MT	17,580	16,718	19,095	30,780	24,624
Countries attracting ADD	MT	11,976	12,222	15,443	16,339	13,071
Other Countries	MT	731	1,797	5,861	6,741	5,393
Total	MT	30,287	30,737	40,399	53,860	43,088
Imports from subject countries						
In Relation to Total Imports	%	58.04	54.39	47.27	57.15	57.15
In Relation to Indian						
Consumption	%	40.31	36.33	35.09	42.52	42.52
In Relation to Indian Production	%	131.99	109.38	136.18	166.05	166.05

- 50. From the above, the Authority notes that:
- i. The imports from China PR have consistently increased throughout the injury period. During the annualized POI, it has registered an upward trend.
- ii. The share of imports of the product under consideration from China PR out of the total imports is quite huge throughout the injury period including the POI.
- iii. Imports from subject country as a whole have remained significant in relation to production and consumption in India.

PRICE EFFECT

Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of Annexure III of the Anti-dumping Rules. The position is as follows:

Price Undercutting and Underselling

52. The Authority has made price undercutting and price underselling analysis both with and without antidumping duty after evaluating the Landed Value of inputs under the duty free imports for the reasons as mentioned in the foregoing paras.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
		***	***	***	***
Net Selling Price	Rs./MT				
		74,293	75,240	77,815	83,783
Landed Value	Rs./MT				
		***	***	***	***
Price undercutting	Rs./MT				
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	0-10	0-10	0-10	0-10

53. The above data indicates price undercutting, without taking into account the antidumping duty in force, is significant.

Price Underselling

54. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out non-injurious price of the subject goods and compared the same with the landed values of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. For examining the underselling effects of the dumped imports the landed value of imports as per para 52 above, without taking into account the antidumping duty in force, has been compared with the Non Injurious Price determined.

Particulars	Unit	POI
Non-Injurious Price	US\$./MT	***
Landed Value	US\$./MT	***
Price underselling	US\$./MT	***
Price underselling	%	***
Price underselling	% Range	20-30%

From the above table, the Authority notes that during the POI, the price underselling was positive for China.

Price suppression and depression effects of the dumped imports:

55. To examine whether the domestic prices are suppressed or depressed due to the presence of dumped imports from subject country the trend of weighted average sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales and the landed values as mentioned in Para 52 above.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Landed Value	Rs./MT	74,293	75,240	77,815	83,783
Trend	Indexed	100	101	105	113
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	134	167
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	103	113

56. From the above information, the Authority notes that there was significant increase in both cost of sales as well as selling price over the injury period. However, the increase in selling price was not in proportion to the increase in cost of sales over the injury period. This shows price suppression effect whereby the domestic industry has not been able to increase the selling price commensurate with increase in the cost of sales.

Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry

57. Annexure II to the Antidumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential

negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Capacity, production, capacity utilization and sales

58. Performance of the domestic industry with regard to production, sales, capacity and capacity utilization are as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Annualized POI
Capacity	MT	15,000	15,000	15,000	18,750	15,000
Production	MT	13,938	15,280	13,998	18,102	14,482
Capacity Utilization	%	92.92%	101.87%	93.32%	96.54%	96.54%
Domestic Sales	MT	13,319	15,284	14,166	18,558	14,847

- 59. From the information given above, the Authority notes that the capacity of the Domestic Industry has remained the same throughout the injury period. However the petitioner submitted that in view of the demand supply gap of Melamine in the country, the petitioner is in the process of expansion of its capacity further by 40,000MT. The production, sales and capacity utilization of the domestic industry has increased in POI as compared to both base year and preceding year.
- As regards the argument that GSFC is unable to meet the demand in India and there is wide demand supply gap, it is noted that the purpose of anti-dumping duty is to redress unfair trade practices and not restrict imports of the product under consideration in Indian market. It is further noted that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers. The Authority refers to its past consistent position in this regard and also relies upon the decision of the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority. If the exporters want to supply the goods to meet the requirement in Indian market that could be done by exporting the requirement at un-dumped prices.

Inventories

61. From the information given below, the Authority notes that the inventory position of domestic industry has declined during period of investigation.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	183	160	75

Profits, return on investment and cash flow

62. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow over the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Annualised POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	134	167	167
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	103	113	113
Profit/(Loss)	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	28	-18	-18
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	29	-20	-20

PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	31	-19	-19
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	38	-6	-6
					_	~
ROCE	%	***	***	***	***	***

63. From the above information, the Authority notes that Profit/Loss and profitability of domestic industry has deteriorated throughout the injury period. Whereas both cost of production and selling price increased over the period, the increase in the cost of production was more than the increase in selling price. Resultantly, the profitability of the domestic industry steeply deteriorated over the injury period. The domestic industry started suffering financial losses during period of investigation. Similarly, the cash profits and return on capital employed also followed the same declining trend.

Employment, wages and productivity

64. From the information given below, the Authority notes that the employment position of the domestic industry has increased during period of investigation as compared to base year. Wages paid have declined in period of investigation as compared to base year but increased as compared to the preceding year. Productivity in terms of production per day and production per employee remained within the same range over the period.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Annualized POI
Employment	Nos.	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	98	104	104
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	50	86	86
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	100	104	104
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	102	100	100

Magnitude of dumping

65. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the China PR is not only positive but also significant.

Growth

66. The Authority notes that the growth of domestic industry in terms of sales, production, and capacity utilization was positive whereas growth in respect of profits, return on investment and cash profits was negative.

Growth	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
In Production	%	-	9.63	(8.39)	3.46
In Domestic Sales	%	-	14.75	(7.31)	4.80
In Capacity Utilization	%	-	9.63	(8.39)	3.46
In Cost of Sales	%	-	***	***	***
In Selling Price	%	-	***	***	***
In Profit /Loss	%	-	***	***	***
In ROI %	%	-	***	***	***

Ability to raise Capital Investment

67. The domestic industry contended that it has planned capital investment of Rs.*** crores, which is for a number of products. This includes substantial capacity expansion for Melamine. The company has argued that it intends to enhance the capacity for Melamine by 40,000 MT. The domestic industry argued that continued dumping of Melamine is adversely impacting the expansion plan of the company with regard to the product. It is noted that

continued dumping of the product and financial losses in the product are bound to adversely impact the ability of the domestic industry to raise capital investments. Though the domestic industry is a multi-product company, the adverse impact on the operating performance of the domestic industry on account of this product could affect the ability of the domestic industry to raise capital investment for the subject goods

Causal Link

68. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

Volume and prices of imports from third countries

69. The Authority notes that during POI, imports of the subject goods from countries other than the subject country are either attracting anti-dumping duty or are not significant.

Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

70. The Authority notes that there is no contraction in the demand during injury period. Demand for the product has increased over the injury period.

Developments in technology

71. The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the DI.

Conditions of competition and trade restrictive practices

72. The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the sole producer of the subject goods.

Export performance of the domestic industry

73. The export performance of the domestic industry is not relevant since price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

Performance of other products

- 74. Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. The petitioner has provided information which pertains only to the product under consideration. Thus, the financial information provided with regard to product under consideration clearly shows the position of the domestic industry with regard to like article produced and sold by the domestic industry.
- 75. The Authority concludes that while the known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined, the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports in the event of cessation of anti dumping duty.
 - i. The volume of imports of the subject goods from the subject country is quite significant.
- ii. Imports of the subject goods from the subject country are undercutting domestic industry's prices.
- iii. The consumers switching over to the imported product would imply decline in demand for the domestic industry product and increase in demand for the dumped product.
- iv. Despite the existence of anti-dumping duties in force on the imports of the subject goods from the subject country, significant volume of dumped imports continues from this source. This indicates that should the measures be allowed to expire, dumping will intensify and cause further injury to the domestic industry.
- v. In case of cessation of anti dumping duties the subject country exporters shall be able to further capture the market in view of their high production capacities and low export prices.

Conclusion on Injury and Causation

76. The investigation has thus shown that the volume of dumped imports from China PR has increased consistently throughout the injury period. With regard to the effect of the dumped imports on prices, there has been significant price undercutting and underselling effect by the dumped imports from China PR as compared with the price of like product in India, and the effect of such imports was to suppress prices to a significant degree. With regard to consequent impact of the dumped imports from China PR on the domestic industry, the investigation has shown that performance of the domestic industry has deteriorated significantly in terms of parameters such as market share, profits, cash profits and return on investment. The investigation has thus shown that the domestic industry has suffered injury from the dumped imports of subject goods from China PR

Magnitude of Injury and Injury Margin

77. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during POI. Further, the Authority has verified the financial records of Domestic Industry to ensure that APM gas has not been diverted for manufacturing of Melamine and that only non APM gas has been used in the manufacturing of Melamine. The injury margin determined for subject country, during POI is as follows:

Particulars	Unit	China PR (POI)		
Non-Injurious Price	US\$./MT	***		
Landed Value	US\$./MT	***		
Injury Margin	US\$./MT	***		
Injury Margin	%	***		
Injury Margin	% Range	20-30		

From the above table, the Authority notes that during POI, the injury is positive and significant.

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

- 78. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
- 79. The Authority notes that in the present investigation, there is continuous dumping of the subject goods from China PR, causing continued injury to the domestic industry, which ipso facto indicates likelihood of dumping and injury from subject country. In view of the above position and due to favourable market conditions prevailing in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority has reason to believe that in the event of revocation/cessation of anti-dumping duties, dumping may intensify from China PR. The following analysis would show about the likelihood of continuation/intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of anti-dumping duties:

(i) Level of current and past dumping margin

80. The level of dumping margin in respect of China in the earlier as well as present investigations is significant. Given the level of price undercutting and price underselling effects from the imports of subject goods from China PR, the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty. The dumping margin in the original investigation final findings were determined in the range of ***%-***% and in the sunset review investigation the dumping margin determined was around ***%.

(ii) Anti-dumping duty European Union

81. European Union has imposed anti-dumping duty against the imports of subject goods from subject country. The Authority notes that Chinese are exporting the product to third countries at dumped prices and the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty.

(iii) Price undercutting, suppression, depression in the absence of measures

82. The prices at which subject goods are being imported from China PR are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in the event of revocation/cessation of the anti-dumping duties, it is likely that exporters from these countries may channelize their output in the Indian market in view of the significant capacities being held by them.

(iv) Huge production capacity in the subject country

83. The evidence provided by the domestic industry, shows nameplate capacity in China for melamine is around 1.8m tonnes/year against the consumption of around 1m tones/year which implies the average plant operating rate is at 50-60% and thus evidences the existence of excess capacities in China PR.

(v) **Dumping margin in respect of exports to third countries**

84. The evidence submitted by the domestic industry on record shows that the producers/ exporters in China are exporting huge volume of subject goods to third countries at dumped prices.

Conclusion on Likelihood of dumping and injury

85. Considering the current level of imports from the subject country despite the imposition of anti dumping duties, the Authority concludes that there exists likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty. It is further noted that the import prices had undercut the domestic prices and also have a significant suppressing effect on the domestic prices.

Post disclosure submissions of the interested parties

86. The authority notes that the disclosure statement was sent to the domestic industry and other interested parties. The following comments have been filed by M/s TPM (on behalf of the domestic industry), M/s Lakshmikumaran & Sridharan (on behalf of M/s Eximcorp), M/s E&Y (representing M/s M/s Century Plyboards (India) Ltd., M/s Bloom Dekor Limited, M/s Meghdoot Laminart Pvt. Ltd., Laminate Manufacturers Association) and M/s Sandeep Organics.

Comments by Domestic Industry

- 87. M/s Balaji Action Buildwell has filed significantly delayed submissions on 30th October, 2015. At the 11th Month as well, the interested party has only filed its opposition and has not filed any information which they are required to file in the form of importer's questionnaire response. Entire submission made by M/s Balaji Action Buildwell deserves to be rejected in light of the Trade Notice No. 01/2012 dated 9th January 2012, time limits specified in the Initiation Notification, past practice of Designated Authority and various WTO Panel and Appellate Body reports.
- 88. The anti dumping duty may be imposed as fixed quantum of anti dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty in US\$/kg. in order to serve the purpose for which anti dumping duties are imposed. There has been significant increase in raw material prices, which led to increase in export price because of increase in cost. However reference price remained same, and therefore anti dumping duty has become totally ineffective. NIP is significantly higher than reference price due to increase in raw material cost

Comments by Importers, Consumers and other Interested Parties on disclosure statement

- 89. The Authority is requested to examine whether the petitioner, who imports from the subject country under review or from other countries, deserves the protection of the Anti-dumping Duty, particularly in light of Rule 2(a) of the Indian AD Rules and Article 4.1 of the WTO AD Agreement recognize the fact that importers of the subject goods may be excluded from the definition of domestic industry.
- 90. The claim of the domestic industry (DI) that the imports under the advance license mechanism are governing the price of the domestic industry and the market as a whole merits summary rejection.
- 91. Before constructing the Normal Value, the Authority is also required to examine the level of trade by Chinese manufacturers and the domestic producer in India. The domestic producer in India has limitation on production and sales due to licensing of its technology to produce. Whereas the Chinese producer uses their own technology and knowhow and free to decide about production, sales and export.
- 92. The DGCIS data is representative of the price at which imports of the subject goods are entering India and this is further substantiated by a report by the Ministry of Chemicals and Petrochemicals on the imports of the subject goods in the most recent period exhibits a much higher import price as compared to even the DGCIS data.
- 93. Reliance on an Alert Circular by the DRI to exclude $2/3^{rd}$ of the import transaction is erroneous as issuance of an Alert circular by DRI merely is a cautionary direction to field formations and nothing else. DRI findings are not over/concluded and the matter is sub-judice. DRI has not issued show cause. Also the DRI Alert as submitted by GSFC was not on their or their representative's letter head.
- 94. It has been the consistent practice of the Authority to use non-duty free import prices for the dumping and injury analysis and there exists no rationale for changing its practice in the subject investigation.
- 95. It is not clear when the domestic producer specifically stated that it has not claimed any volume injury as it has not any such injury, then why the Designated Authority examined such volume injury and came to the conclusion that in fact such injury exist.
- 96. There exists a huge demand and supply gap in India as regards the subject goods. Therefore, the proposition that because the imports of the subject goods from China have been significant despite the imposition of anti-dumping and hence the duty ought to be continued is grossly fallacious.
- 97. Adopting the import price of only duty free imports as per DG Systems data is inappropriate for determining dumping margin and injury margin. All import (duty & duty free) data should be considered along with export data.
- 98. Import of melamine is of syntan grade and the weighted average sales realization for the purpose of comparison is not fair.
- 99. The domestic producer is procuring the raw material from a source which is overcharging it. The main raw material is available to the domestic producer at very low price for manufacturing fertilizers. Therefore, the use of highly inflated price of raw material is illegal.
- 100. Respondent questions the basis of the Authority's conclusions that performance of the domestic industry has deteriorated significantly when market share of the domestic producer increases in a situation (i) where demand of the subject goods increases; (ii) domestic producer is operating at near 100% production capacity and able to sale whole; and (iii) imports takes place to fill the gap in consumption and supply by the domestic producer.
- 101. The Authority is also requested to take into account that there have been shut-downs in M/s GSFC, and in present it is expanding its capacity, importing the subject goods from Qatar and enjoys monopolistic situation.

- 102. The injury to domestic industry has occurred from factors other than dumping, which must be quantified and separated before arriving at any fair comparison, as has been laid down by the WTO's DSB Appellate Body in the *US-Hot Rolled Steel_*matter.
- 103. The Designated Authority recommends duty in terms of US Dollar, though the currency of India is INR. The ADA does not provide for imposition of Anti-dumping Duty in terms of currency of other countries.
- 104. Even while converting the NIP to US Dollars, the Authority conferred windfall gains on the domestic industry by taking into account highly depreciated Indian Rupee. The Authority must rather take into consideration the current conversion rate and not that one that was prevalent during the POI.
- 105. The Authority may prescribe a method to link the reference price with index of the raw material, so that the duty collection should not exceed the prevalent injurious dumping margin.
- 106. It is incorrect on the part of the domestic industry to claim that the form of duty should be in the form and manner as requested. The form of duty is expected to be chosen by the Hon'ble Authority after taking into cognizance interests of all the stakeholders on the subject and merits of each case.
- 107. Despite global fall in the prices of Natural gas and urea, existence of anti dumping duty still continues on the subject goods on the basis of rigged data.
- 108. Landed cost of imports is higher and importers are suffering losses; and there should not be any change in ADD, as already this product has ADD for more than 10 years.
- 109. Fixation of NIP for 5 years is arbitrary and absurd. This should be reviewed and changed every three months in line with the indexed cost of sole input that goes in to making of the final product. Fixing a NIP disproportionate on whimsical and doctored/fabricated data is conduct unbecoming of the position the Authority holds.
- 110. If the import of the subject goods by the petitioner was casual and only to fulfill the gap when the facility was shut down, then why was AD duty allowed to operate during the time of the shut down because there was no injury to them as such during the closure periods.
- 111. In law, there is no concept of public or oral hearing, rather the obligation is to hear and this refers to personal hearing against the issues framed. We must know what Authority's exact finding is before a rebuttal or counter view is pressed.
- 112. Cost of production as reflected in the value of closing stock of the DI is a public document; and the Authority may also provide a reason for keeping the *artificial* landed price as confidential.
- 113. The proceedings are carried out administratively rather than quasi judicially, and also Preliminary finding should be issued by the Authority.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 114. The Authority notes that M/s GSFC, the domestic producer has imported the subject goods from non subject countries and not from the subject country to an extent of 13.48% in relation to production, 4.53% in relation to total imports and 3.37% in relation to Indian consumption in the POI.
- 115. The Authority notes that in the Final Finding dated 01st June' 2012 of the same product from EU, Iran, Indonesia and Japan, similar level of imports was made by the DI. The Authority in that final determination had also held that even though M/s GSFC had imported and sold the subject goods, the focus of M/s GSFC has not turned to imports and the company is not behaving like an importer trader. The focus of the company continues to be that of a producer and do its own production. The Authority holds that M/s GSFC's behaviour even now is that of a producer and that it also has its plans to enhance its production capacity further by 40,000 MT.
- 116. The Authority in the instant investigation in view of nil imports of the subject goods from the subject country in the POI, holds that M/s GSFC constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b).
- 117. The Authority holds that the grades and quality issues raised have not been demonstrated and quantified by the interested parties with any data or evidence. None of the producers/exporters from China PR have cooperated and provided any response on these issues. The Authority notes that the product under consideration has not been segregated into different grades and that the goods imported from subject country and the goods manufactured by the domestic industry are held as 'like article'.
- 118. As regards contentions of various interested parties on referencing the import price under advance license route, the Authority holds that most of the non- advance license route import prices do not appear to be fair and realistic in light of the DRI's investigation. The Authority has noted that the export prices to India available under the

China Customs data correlate only with the import prices to India under Advance License route and not with the non advance license route. The Authority has held consistently in past that even the prices under advance license lead to injury since even these imports adversely affect the opportunities available to domestic industry to increase their supplies to exporters and to that extent, the demand of the subject goods also declines. It is also noted that it is the consistent practice of the Authority to include imports under duty exemption for the purpose of assessment of injury to the domestic industry.

- 119. As regards Normal Value, the submission on the production technology and cost advantage of Chinese goods by various interested parties, mainly importers, cannot be considered as none of the producers/ exporters from China has cooperated. Without any response on manufacturing process and production details, the Authority has no choice but to use best available information.
- 120. In view of the above, the Authority has constructed the normal value in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules in accordance with its consistent practice by using the best available information on referring the best utilization norm of the raw materials and the optimum cost of utilities, conversion cost, SGA expenses and interest cost of domestic industry.
- 121. The Authority further notes that the quantity of imports of subject goods in Period of Investigation as available under DGCI&S, DG Systems and China Customs by and large correlate. Thus the injury evaluation on volume effect based on the import quantity of the subject goods from the subject country for various volume related parameters does not vary the data available under the three sources.
- 122. For the price effect, in view of the over invoicing phenomenon adopted by importers as also investigated and reported by DRI, the Authority has adopted the prices of advance license route which broadly correlates with the China Customs data.
- 123. The Authority further holds that the landed value of imports as per the CIF prices adopted in the investigation is appropriately correlated with China custom export price (WTA data). This has led to significant undercutting and a significant injury margin. As dumping and consequential injury are continuing in the POI, the Authority holds that the withdrawal of the ADD may lead to reoccurrence of dumping of the subject goods from the subject country.
- 124. The Authority notes that the same interested parties have made submissions on the procedure of carrying out investigation, especially public hearing, procedure being administrative in nature rather than quasi judicial; data in China not being verified irrespective of cooperation; etc. The Authority holds that the entire investigation was carried out strictly as per AD Rules and by adopting consistent practice on procedural issues with no exceptions. The non-cooperating producers/ exporters have been treated strictly in accordance with the stipulated Rules. The Authority holds that in fact it has made exceptions in the present investigation by accommodating various interested parties to consider their submissions made at an extremely belated stage even though these interested parties did not file requested response in the prescribed form. Thus the investigation has been carried out by observing all possible natural justice principles to the extent they were relevant and were covered under Rules.
- 125. The Authority maintains a public file containing all non- confidential version submissions made by various interested parties for the reference of all interested parties.
- 126. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti dumping measures. On the contrary, imposition of antidumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

RECOMMENDATIONS

- 127. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:
- i. There is continued dumping of the product concerned from China PR, causing injury to the domestic industry.
- ii. Both price undercutting and underselling effects of dumped imports from China PR are positive.
- iii. The financial performance of the Domestic Industry has deteriorated in terms of profitability, return on investment due to price undercutting effect of dumped imports from China PR. These dumped imports continue to cause injury to the domestic industry.

iv. Dumping of the product under consideration from China PR is likely to continue/ intensify should the current antidumping duty be revoked.

Recommendations

- 128. Having concluded as above, the Authority is of the view that the antidumping measure is required to be extended as specified in the duty table below. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry.
- 129. With regard to duty structure, keeping into account factual matrix of the case and having regard to contentions raised, information provided and submissions made by interested parties, it is deemed appropriate to recommend a fixed form of anti dumping duty. Accordingly, the anti dumping duty equal to the amount indicated in the table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Duty Table

S. No.	Tariff Item	Description of goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
1	2933 6100	Melamine	China PR	China PR	Any	Any	331.10	MT	US\$
2	2933 6100	Melamine	Any country other than those subject to antidumping duty	China PR	Any	Any	331.10	MT	US\$
3	2933 6100	Melamine	China PR	Any country other than those subject to anti- dumping duty	Any	Any	331.10	MT	US\$

130. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

Further Procedure

- 131. An appeal against the order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.
- 132. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act, Rules and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

A K BHALLA, Designated Authority